गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 156
दि. 05.10.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

दवा या ज़हर : बच्चों की मौत से हड़कंप और सरकारों की ताबड़तोड़ कार्रवाई

नई दिल्ली। देश भर में पिछले कुछ दिनों से एक ही सवाल गूंज रहा है—क्या बाज़ार में आसानी से मिलने वाली खांसी की दवा, जो बच्चों को राहत देने के लिए दी जाती है, वास्तव में दवा है या ज़हर? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मध्यप्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कफ सिरप पीने के बाद मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। घटनाओं की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दवाओं में ऐसा जहरीला रसायन मिला है, जो मानव शरीर के लिए घातक है और जिसने बच्चों की किडनी फेल कर दी।

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले से शुरुआत हुई, जहां 27 दिन के भीतर 10 बच्चों की मौत हो गई। शुरुआत में मामला सामान्य बीमारी और किडनी फेल होने का माना गया, लेकिन जब मौतों का सिलसिला एक के बाद एक जारी रहा तो स्वास्थ्य विभाग सतर्क हुआ। जांच में सामने आया कि जिन बच्चों को खांसी-जुकाम के लिए कोल्ड्रिफ कफ सिरप दिया गया था, उनमें अचानक किडनी फेल होने लगी। नमूनों की जांच के बाद पाया गया कि दवा में डाईएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) मौजूद था। इसकी मात्रा तय सीमा से कहीं अधिक थी। DEG का उपयोग आमतौर पर औद्योगिक कार्यों में किया जाता है—पेंट, ब्रेक फ्लूड और एंटीफ्रीज़ में। यह मानव शरीर में पहुंचकर ज़हर की तरह असर करता है। बच्चों का शरीर इस ज़हर को झेल नहीं पाया और मौत हो गई।

राजस्थान के भरतपुर और सीकर ज़िलों से भी ऐसी ही खबर आई। यहां डेक्सट्रोमेथॉरफन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप देने के बाद दो बच्चों की मौत हुई। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि मौत की वजह किडनी फेल होना थी और सिरप का सेवन ही इसका कारण बना। इसके बाद सरकार हरकत में आई और जयपुर स्थित केसंस फार्मा की सभी 19 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यही नहीं, राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर को भी निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने पहले इस कंपनी को क्लीन चिट दे दी थी। इसने राज्य की दवा निगरानी व्यवस्था की खामियों को उजागर कर दिया।

तमिलनाडु में भी उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी गई। यहां दवा के बैच नंबर SR-13 की जांच की गई तो पाया गया कि उसमें DEG की मात्रा 48.6% थी। यानी दवा में लगभग आधा हिस्सा जहरीले रसायन का था। इसे देखकर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और फैक्ट्री का उत्पादन रुकवा दिया।

इन घटनाओं ने देशभर में सनसनी फैला दी। जब-जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, लोगों का भरोसा दवा कंपनियों और नियामक संस्थाओं से उठने लगता है। सवाल उठता है कि जब दवा बाजार में पहुंचती है तो क्या उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं होती? अगर होती है तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है?

केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले पर तुरंत संज्ञान लिया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने छह राज्यों में 19 दवा कंपनियों के प्लांट की जांच शुरू की। उद्देश्य साफ था—ऐसी खामियों की पहचान करना और यह देखना कि आखिर किन लापरवाहियों की वजह से बच्चों की जान गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की। उसमें स्पष्ट कहा गया कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी हाल में कफ सिरप न दिया जाए। पांच साल तक के बच्चों को भी सामान्यतः यह दवा न दी जाए। अगर कभी डॉक्टर ज़रूरी समझकर देते हैं तो बच्चे को कड़ी निगरानी में रखा जाए, न्यूनतम खुराक और सीमित दिनों तक ही दवा दी जाए।

यह घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम दवा की आड़ में बच्चों को ज़हर पिला रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए कफ सिरप का उपयोग लंबे समय से होता आया है, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसे पहले से ही प्रतिबंधित किया जा चुका है। इसका कारण यही है कि इन दवाओं के साइड इफेक्ट बच्चों पर बेहद खतरनाक हो सकते हैं।

अब सरकारों की कार्रवाई से भले ही उत्पादन और बिक्री पर रोक लग गई हो, लेकिन जिन परिवारों ने अपने मासूम बच्चों को खो दिया, उनके लिए यह कदम बहुत देर से आया है। वे हमेशा यही सोचेंगे कि अगर निगरानी पहले कड़ी होती, तो उनके बच्चे आज ज़िंदा होते। यह त्रासदी भारत की दवा व्यवस्था और नियामक संस्थाओं के लिए आईना है, जो यह बताती है कि सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, उसके सख्त पालन की ज़रूरत है।

दवा और ज़हर के बीच का फर्क बहुत पतला है। वही दवा जो किसी को राहत दे सकती है, वही दवा ज़रा-सी लापरवाही के कारण मौत का कारण बन सकती है। बच्चों की इन मौतों ने यह साफ कर दिया है कि अब सरकार और समाज दोनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दवा का नाम लेकर किसी को ज़हर न पिलाया जाए।

भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हराया

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से पराजित कर दिया। यह मुकाबला तीसरे ही दिन समाप्त हो गया, जहाँ भारतीय टीम ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से एकतरफा दबदबा दिखाया। इस जीत के साथ ही भारत ने दो मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली और घरेलू सत्र की शुरुआत शानदार अंदाज़ में की।

मैच की शुरुआत में भारतीय बल्लेबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने मजबूत स्कोर खड़ा किया, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका रवींद्र जडेजा के शतक की रही। जडेजा ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक खेलते हुए नाबाद शतक जड़ा। उनकी बल्लेबाज़ी में धैर्य, संयम और ज़रूरत पड़ने पर आक्रामकता का भी बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। टीम इंडिया की पारी में अन्य बल्लेबाज़ों ने भी योगदान दिया, लेकिन जडेजा का प्रदर्शन टीम को विशाल बढ़त दिलाने में निर्णायक साबित हुआ।

वेस्टइंडीज की पहली पारी भारतीय गेंदबाज़ों के सामने बिखर गई। मेहमान बल्लेबाज़ भारतीय गेंदबाज़ी आक्रमण का सामना नहीं कर सके और उन्हें फॉलो-ऑन खेलना पड़ा। दूसरी पारी में भी हालात नहीं बदले। 45.1 ओवर में ही पूरी कैरिबियाई टीम 145 रन पर सिमट गई। वेस्टइंडीज की ओर से ऐलेक ने सर्वाधिक 38 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज़ संघर्ष ही करते रह गए।

भारतीय गेंदबाज़ों ने शानदार तालमेल से काम किया। तेज़ गेंदबाज़ों ने नई गेंद से शुरुआती झटके दिए और उसके बाद जडेजा ने अपनी फिरकी का जादू बिखेर दिया। उन्होंने वेस्टइंडीज की बल्लेबाज़ी को पूरी तरह उलझाकर रख दिया और लगातार विकेट निकालते रहे। उनके सामने विपक्षी बल्लेबाज़ असहाय नज़र आए।

यह जीत भारतीय टीम के लिए सिर्फ एक शानदार आगाज़ नहीं बल्कि घरेलू मैदान पर उनके आत्मविश्वास का सबूत भी है। अहमदाबाद में मिली यह बड़ी जीत यह दर्शाती है कि भारत की टीम टेस्ट क्रिकेट में अभी भी बेहद मज़बूत स्थिति में है। अब सीरीज़ का दूसरा और अंतिम टेस्ट 10 अक्तूबर से दिल्ली में खेला जाएगा, जहाँ भारत का लक्ष्य 2-0 से सीरीज़ जीतने का होगा जबकि वेस्टइंडीज बराबरी करने की कोशिश करेगा।

अमेरिका में एक और भारतीय छात्र की हत्या, परिवार और अधिकारियों में शोक और चिंता

टेक्सास। अमेरिका में भारतीय समुदाय के लिए चिंताजनक घटनाओं का सिलसिला जारी है। टेक्सास के डलास में 28 वर्षीय भारतीय छात्र चंद्रशेखर पोल की शुक्रवार रात एक अज्ञात बंदूकधारी ने हत्या कर दी। चंद्रशेखर पोल हैदराबाद से थे और उन्होंने भारत में डेंटल सर्जरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2023 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका का रुख किया था। हाल ही में उन्होंने अमेरिका में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की थी और पूर्णकालिक नौकरी की तलाश में पेट्रोल पंप पर पार्ट टाइम काम कर रहे थे। घटना के बाद परिवार सदमे में है और उन्होंने अपने बेटे का शव अमेरिका से वापस लाने के लिए भारतीय सरकार से मदद मांगी है। तेलंगाना के बीआरएस विधायक और पूर्व मंत्री टी. हरीश राव ने इस मामले में परिवार का समर्थन किया। उन्होंने शनिवार को छात्र के घर जाकर परिवार से मुलाकात की और उनकी पीड़ा को साझा किया। बीआरएस के अन्य विधायक सुधीर रेड्डी भी इस अवसर पर मौजूद थे। यह मामला पिछले महीने हुए एक और दर्दनाक घटना की याद ताजा कर रहा है। पिछले महीने डलास में ही 50 वर्षीय भारतीय मूल के मोटल मैनेजर चंद्र मौली नागमल्लैया की उनके सहकर्मी योडानिस कोबोस-मार्टिनेज ने हत्या कर दी थी। उस समय घटना मोटल के डाउनटाउन सूट्स में हुई थी, और संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस मामले में चंद्र मौली की हत्या उनके परिवार के सामने हुई थी, जिससे समुदाय में गहरा शोक और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। चंद्रशेखर पोल की हत्या ने भारतीय छात्रों और प्रवासियों में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी प्रशासन इस घटना की जांच कर रहा है और स्थानीय पुलिस ने बताया है कि संदिग्ध की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है। इस बीच, भारतीय समुदाय और अधिकारियों ने परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और मृतक छात्र की याद में शोक जताया। यह घटनाक्रम यह दर्शाता है कि विदेशों में अध्ययन और काम करने वाले भारतीय युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना कितना आवश्यक है। भारतीय नागरिकों के अधिकारों और उनके सुरक्षित रहने की जिम्मेदारी पर भी यह मामला गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है।

यूपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा के बाद अंतरिम आंसर-की प्रकाशित करने का निर्णय लिया

नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट किया कि अब वह प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने के बाद अंतरिम आंसर-की प्रकाशित करेगा। यह निर्णय सिविल सेवा परीक्षा सहित आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और उम्मीदवारों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। हलफनामे में यूपीएससी ने बताया कि यह कदम एक लंबित याचिका के संदर्भ में उठाया गया है, जो सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ी थी। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायमित्र के सुझावों के साथ ही अन्य कारकों पर भी विचार-विमर्श किया। वकील वर्धमान कौशिक ने बताया कि इस निर्णय में यूपीएससी की संवैधानिक जिम्मेदारी और उम्मीदवारों के हित दोनों का ध्यान रखा गया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम आंसर-की प्रकाशित करने का उद्देश्य उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम और अंकांकन के संदर्भ में प्रारंभिक जानकारी देना है। इससे उम्मीदवार अपनी तैयारियों और भविष्य की रणनीति का आकलन कर सकेंगे।

ट्रेन और ऊर्जा नेटवर्क पर रूस का भीषण हमला : 30 घायल, 50 हज़ार घर अंधेरे में डूबे

रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध ने एक बार फिर से नागरिकों को सीधा निशाना बना दिया है। यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में रूस द्वारा किए गए ड्रोन हमले ने तबाही मचा दी। एक रेलवे स्टेशन पर हुई इस बमबारी में कम से कम 30 लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की ने इस हमले को "क्रूर" और "नागरिकों को आतंकित करने वाला" बताया। उनका कहना है कि रूसियों को पता था कि वे यात्री और रेलवे कर्मचारियों पर वार कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें ट्रेन के डिब्बे आग की लपटों में घिरे दिखाई दे रहे हैं। रेलवे नेटवर्क यूक्रेन के युद्धकालीन ढांचे में बेहद अहम है, क्योंकि इसी से सैनिकों और राहत सामग्री का परिवहन किया जाता है। यही कारण है कि संघर्ष की शुरुआत से रूस लगातार रेलवे लाइनों को निशाना बना रहा है। सुमी में यह हमला रूस की सीमा से महज़ 50 किलोमीटर दूर हुआ, जिससे यूक्रेनी सुरक्षा की कमजोर कड़ी भी उजागर हुई।

इसी हमले के साथ रूस ने एक और रणनीतिक वार किया और यूक्रेन के ऊर्जा नेटवर्क को तहस-नहस करने की कोशिश की। चेरनिहिव शहर में ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया गया, जिसके कारण करीब 50,000 घर अंधेरे में डूब गए। रात भर चली मिसाइल और ड्रोन बौछार के बाद कई जगह आग लग गई। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि रूस का असली मकसद ठंड के मौसम से पहले यूक्रेनियों को बिजली, गर्माहट और पानी से वंचित करना है।

यूक्रेनी वायु सेना ने बताया कि शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक रूस ने 381 ड्रोन और 35 मिसाइलें दागीं। इनमें से बड़ी संख्या में हमले सीधे नागरिक ढांचे पर किए गए। यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने 73 ड्रोन को मार गिराया, लेकिन जो बचे, उन्होंने भारी नुकसान पहुँचाया। इससे पहले रूस ने नाफ्तोगाज, यूक्रेन की सबसे बड़ी गैस कंपनी, की सुविधाओं पर भी हमला किया था।

प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको ने रूस पर आरोप लगाया कि यह सब जानबूझकर नागरिकों को आतंकित करने के लिए किया जा रहा है। वहीं रूस का कहना है कि उसके हमले कीव की युद्ध-समर्थक सुविधाओं को नष्ट करने के लिए हैं।

गौरतलब है कि फरवरी 2022 से शुरू हुए इस युद्ध में रूस हर साल सर्दियों से पहले यूक्रेन की बिजली आपूर्ति पर हमले करता रहा है। इसका सीधा उद्देश्य लोगों को कठिन परिस्थितियों में डालकर उनकी सरकार और युद्ध के प्रति समर्थन को कमजोर करना है। इस बार उसने रेलवे और ऊर्जा दोनों नेटवर्क पर एक साथ वार किया है, ताकि यूक्रेन के सैन्य और नागरिक जीवन को एक झटके में पंगु किया जा सके।

इस हमले के बाद साफ है कि युद्ध थमने के कोई आसार नहीं दिख रहे। रूस लगातार अपने हमले तेज कर रहा है और यूक्रेन अपने ढांचे को बचाने की जद्दोजहद में जुटा है। सर्दियों के आगमन से पहले यूक्रेन की जनता के सामने अंधेरा, ठंड और भय—तीनों की त्रासदी एक साथ खड़ी हो गई है।

रूस-पाकिस्तान सैन्य सौदे पर भारत में सियासी तूफान, कांग्रेस ने पीएम मोदी से मांगा जवाब

नई दिल्ली। रूस और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य सौदे को लेकर भारत में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को केंद्र सरकार से तीखे सवाल उठाए और मोदी सरकार की विदेश नीति पर गंभीर आपत्ति जताई। पार्टी ने इस सौदे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत छवि आधारित कूटनीति की विफलता बताया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत का कभी सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार रहा रूस अब पाकिस्तान को सैन्य मदद क्यों दे रहा है।

रमेश ने विशेष रूप से यह आरोप लगाया कि रूस ने भारत की अपीलों को अनदेखा करते हुए पाकिस्तान के लिए चीन निर्मित जेएफ-17 लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होने वाले एडवांस इंजन RD-93MA की सप्लाई जारी रखी है। उन्होंने कहा कि यही विमान भारत के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान इस्तेमाल किए गए थे। इसके अलावा रमेश ने जून महीने में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के हस्तक्षेप के बावजूद सौदे को आगे बढ़ाने को भी चिंता का विषय बताया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि जब भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है और Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट्स पर बातचीत कर रहा है, तब रूस का पाकिस्तान को हथियार देना भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी विदेश नीति केवल इवेंट और फोटो खिंचवाने तक सीमित रह गई है, जिससे भारत को वास्तविक लाभ नहीं मिल रहे हैं।

रमेश ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने में विफल रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर, जिन्होंने हाल ही में सांप्रदायिक भड़काऊ बयान दिए, उन्हें ट्रंप जैसे नेताओं का समर्थन प्राप्त है और रूस द्वारा हथियार भी मिल रहे हैं। वहीं, चीन भी पाकिस्तान के पूर्ण समर्थन में खड़ा है। कांग्रेस ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है कि भारत के पुराने भरोसेमंद साथी रूस ने पाकिस्तान के पक्ष में ऐसा रुख क्यों अपनाया और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। इस मुद्दे ने न केवल संसद और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर गंभीर बहस का विषय भी बन गया है।

महाराष्ट्र में ओबीसी संगठनों ने श्वेत पत्र की मांग की, फडणवीस के साथ बैठक में उठे मुद्दे

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में शनिवार को सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित बैठक में राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) संगठनों ने मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने वाले सरकारी आदेश का विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की। ओबीसी संगठनों का कहना था कि यह आदेश 2 सितंबर को जारी किया गया था और उनके हितों के खिलाफ है। उन्होंने विशेष रूप से यह भी कहा कि आदेश मनोज जरांगे के नेतृत्व में पांच दिवसीय आंदोलन के बाद जारी किया गया, जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते।

बैठक में ओबीसी संगठनों ने 2014 से अब तक राज्य में जारी सभी जाति प्रमाणपत्रों और जाति वैधता प्रमाणपत्रों पर पारदर्शिता और कानूनी वैधता सुनिश्चित करने के लिए 'श्वेत पत्र' प्रकाशित करने की भी मांग की। उनका मानना है कि श्वेत पत्र से प्रशासनिक प्रक्रिया स्पष्ट होगी और जातिगत विवादों को रोका जा सकेगा।

बैठक में शामिल कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि राज्यव्यापी ओबीसी रैली 10 अक्टूबर को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने अभी तक उनकी दो प्रमुख मांगों—सरकारी आदेश को वापस लेना और श्वेत पत्र प्रकाशित करना—पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार कानूनी ढांचे के भीतर हर समुदाय को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जाति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी है और प्रमाणपत्रों की वैधता सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन प्रणाली और वंशावली समिति बनाई गई है। फडणवीस ने यह भी बताया कि इस महीने 'महाज्योति' योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं और राज्य में ओबीसी समुदाय के लिए कुल 63 छात्रावास स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल की योजनाओं का लाभ अन्य पिछड़े वर्गों तक भी पहुंचाया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसी एक समुदाय को आरक्षण मिलने से अन्य समुदायों के अधिकारों का हनन नहीं होगा और सभी निर्णय कानून के दायरे में होंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि झूठे दस्तावेज देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी समुदाय के साथ अन्याय न होने का सुनिश्चित करना है। बैठक में मंत्री, सांसद, विधायक और सामाजिक न्याय एवं पिछड़ा कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस बैठक ने ओबीसी संगठनों और सरकार के बीच संवाद की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि दोनों पक्षों के बीच अभी भी कुछ मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि सरकार समुदायों के हितों और कानूनी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने के प्रयास में है।

संपादकीय

मौत का सिरप

कैसी विडंबना है कि जीवन रक्षा के लिये दी जाने वाली दवा मौत का कारण बन जाए। जो दवा की संदिग्ध गुणवत्ता और निर्माता कंपनियों की आपराधिक लापरवाही को ही उजागर करती है। जाहिर है रसायनों की घातकता की मात्रा और गुणवत्ता में कोई खोट इस तरह के हादसों का सबब बना होगा। राजस्थान में कुछ बच्चों की मौत की वजह का संबंध उस सिरप से बताया जा रहा है, जो खांसी ठीक करने के लिये दिया गया। ये हादसे इस बात को रेखांकित करते हैं कि दवा की गुणवत्ता में चूक सामान्य उपचार को कितने जानलेवा जोखिम में बदल सकती है। बताया जाता है कि बच्चों को कथित रूप से मुख्यमंत्री की मुफ्त दवा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में एक जेनेरिक खांसी की सिरप दी गई थी। जबकि इस मामले में जांच चल रही है, यह त्रासदी भारत की फार्मास्यूटिकल निगरानी तंत्र की कोताही ही उजागर करती है। खासकर हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में, जो फार्मा हब के रूप में प्रमुख रूप से उल्लेखित है। महत्वपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश की 655 फार्मास्यूटिकल इकाइयों में से केवल 122 ही जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज के संशोधित शेड्यूल एम मानकों के तहत अपग्रेड करने के लिये पंजीकृत हैं। इसका मतलब यह है कि अधिकांश फार्मा इकाइयां गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को प्रमाणित किए बिना काम कर रही हैं। ये जनस्वास्थ्य के प्रति कितनी गैरजिम्मेदार स्थिति है। जबकि हकीकत यह है कि फार्मास्यूटिकल इकाइयों को अपग्रेड करने की समय सीमा कई बार बढ़ाई गई है। यह नियामक तंत्र की कमजोरियों और छोटी फर्मों में सुरक्षित प्रक्रियाओं में निवेश करने की अनिच्छा को ही उजागर करती है। यह विडंबना ही है कि हमारा तंत्र जन-स्वास्थ्य के खिलवाड़ के प्रति उदासीन बना हुआ है। निस्संदेह, जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया, उनके लिये यह बहस कोई सांत्वना नहीं है। उन्हें सही मायनों में सांत्वना तभी मिलेगी जब आपराधिक लापरवाही करने वालों को दंडित किया जाएगा।

विडंबना यह है कि अतीत में भी ऐसी कई त्रासदियां हुई हैं, लेकिन हमारे तंत्र ने इससे कोई सबक नहीं सीखा। हालांकि शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को परामर्श जारी किया है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाइयां नहीं दी जाएं। वर्ष 2020 में भी एक ऐसी त्रासदी सामने आई थी, लेकिन कुछ दिन के शोर के बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। विडंबना देखिए कि मृत बच्चों के परिजन आज भी न्याय की प्रतीक्षा में आंसू बहा रहे हैं। हकीकत यह है कि ऐसी मौतों की जिम्मेदारी तय करने में लगातार देरी होती रहती है। ऐसे हादसों को या तो कमतर दर्शाया जाता है या फिर पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि विगत में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। भारत की फार्मा कंपनियों के द्वारा तैयार सिरप से गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत का लिंक पाए जाने के बाद भारतीय दवाओं पर प्रतिबंध लगाए गए थे। निस्संदेह, ऐसे गैर-जिम्मेदार तरीके से तैयार दवाइयों के चलते भारत की 'विश्व की फार्मेसी' के रूप में हासिल प्रतिष्ठा को ही नुकसान पहुंचा है। हमारे नियामक तंत्र को और कितने बच्चों के मरने का इंतजार है.. जरूरी है इससे पहले गुणवत्ता नियंत्रण सिर्फ कागज पर नहीं व्यवहार में लागू करने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने दवाइयों के गुणवत्ता मानकों को तय करने के लिए सख्त तरीके जीएमपी अनुपालन हेतु समय-समय पर निरीक्षणों के लिये कदम उठाए हैं। लेकिन प्रवर्तन के स्तर पर अभी भी तमाम खामियां बरकरार हैं। विडंबना यह है कि राज्य नियामकों के पास पर्याप्त संसाधनों का अभाव है। साथ ही अकसर दंड के प्रावधान प्रभावी नहीं होते। यह एक कटु सत्य है कि भारत की फार्मा सफलता की कहानी केवल सस्ती जेनेरिक दवाइयों पर आधारित नहीं रह सकती। हमें इसे विश्वसनीय बनाने की जरूरत है। इसके लिए मजबूत ऑडिट, लापरवाही के लिए आपराधिक जिम्मेदारी तय हो और मामलों में पीड़ितों को तीव्र न्याय मिलना चाहिए। अन्यथा, ऐसी हर त्रासदी जन-विश्वास को कमजोर करती है- जो किसी भी दवा में सबसे महत्वपूर्ण घटक है।

अमेरिकी अविश्वास से बनते नए कूटनीतिक समीकरण

> अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से क्या विश्व कूटनीति में नये समीकरण उभर रहे हैं, नई दोस्तियां हो रही हैं, नए समझौते हो रहे हैं इनके केंद्र में पश्चिमी एशिया व एशिया है, जहां के देशों के बीच पुनर्मिलन व नई संरचनाएं हो रही हैं। इसमें से न्यू वर्ल्ड ऑडर भी आकार ले सकता है। विश्व व्यापार में जी-7 देशों का दबदबा कम होना और जी-20 का प्रभाव बढ़ना क्या इसका सूत्रधार है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से क्या विश्व कूटनीति में नये समीकरण उभर रहे हैं, नई दोस्तियां हो रही हैं, नए समझौते हो रहे हैं इनके केंद्र में पश्चिमी एशिया व एशिया है, जहां के देशों के बीच पुनर्मिलन व नई संरचनाएं हो रही हैं। इसमें से न्यू वर्ल्ड ऑडर भी आकार ले सकता है। विश्व व्यापार में जी-7 देशों का दबदबा कम होना और जी-20 का प्रभाव बढ़ना क्या इसका सूत्रधार है।

ये तमाम सवाल ट्रंप के रोज नए पैंतरों और उनके जवाब में देशों के झुकने के बजाय नये रास्ते निकालने से और तेज हो गये हैं। इसके एक ज्वलंत उदाहरण के रूप में, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता दिखाई देता है। जिस तरह से ये दोनों देश—जो अमेरिका के साथ ही माने जाते हैं, वे साथ आए, उससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खलबली मची है। सवाल है कि क्या पश्चिम एशिया के देशों में खासतौर से जो अमेरिका की गुड बुक्स में रहे हैं, उनका भरोसा अमेरिका से हट रहा है। पश्चिम एशिया के देश क्या अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसे ट्रंप द्वारा अफगानिस्तान के तालिबानी शासन पर बगराम एयरबेस को वापस मांगने के लिए धमकी देने वाले घटनाक्रम से भी जोड़कर देखा जा सकता है। जिस तरह से तालिबानी शासन ट्रंप की इस मांग का विरोध कर रहा है—वह उसके वर्चस्व को चुनौती देने जैसा प्रतीत होता है। और तो और ट्रंप ने भारत पर जो एच1बी वीजा की फीस बढ़ाकर 88 लाख रुपये सालाना करके एक और वार किया, उसमें चीन का के-1 वीजा का ऑफर भी इसी सिलसिले में दिखाई देता है।

आखिर पश्चिमी एशिया में ऐसा क्या घट रहा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इतना अहम समझौता किया। दरअसल, इस समझौते के पीछे सबसे बड़ा कारक है कतर पर किया गया इस्राइल का हमला। जिस तरह से इस्राइल ने अच्छी-खासी दूरी को लांघते हुए

कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया—उसने पूरे इलाके में गहरा विक्षोभ व असंतोष पैदा किया। कतर अमेरिका का पुराना सहयोगी देश है और यहां वर्ष 2000 से अमेरिका का सैन्य अड्डा है। कतर की राजधानी दोहा के पास मौजूद अल उदैद एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ते एयर ऑपरेशंस का मुख्यालय है। यानी कतर को यह 100 फीसदी गारंटी थी कि अमेरिका का सैन्य अड्डा यहां है, लिहाजा वह इस्राइल समेत तमाम देशों के किसी भी हमले से महफूज़ है। जब दोहा में हमास के नेताओं को मारने के लिए इस्राइल ने हमला बोला—तब उसका ये विश्वास खंडित हो गया। यहां कतर का यह कहना भी वाजिब है कि वह अमेरिका के कहने पर ही फलस्तीन के मिलिटेंट संगठन हमास के संग शांति वार्ता आयोजित कर रहा था ऐसे में उसकी राजधानी पर इस्राइल का हमला—उसके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। पूरे इलाके में खलबली मची। साथ ही साथ सऊदी अरब को भी लगा कि वह भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस्राइल की मिसाइलें सऊदी के एयर स्पेस को पार करके ही दोहा पहुंच सकती थीं। सऊदी अरब पश्चिमी एशिया में बड़ा देश है और उसे भी गहरी बेचैनी व असुरक्षा लगी। वरना, अभी तक ये सारे देश (मुस्लिम देश) विश्व कूटनीति में अमेरिका के साथ ही माने जाते रहे हैं।

इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी एक तरह से कतर को उसकी औकात बताने के लिए कहा कि उन्होंने ट्रंप को दोहा पर इस हमले के बारे में बता दिया था। यानी इस्राइल ने अपनी बॉसगीरी को छुपाकर नहीं रखा और यह भी कह दिया कि वह आगे भी ऐसा ही करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी मजबूरी में कहना पड़ा कि इस्राइल सही कह रहा है। सऊदी अरब जो इस इलाके का सबसे बड़ा और शक्तिसंपन्न देश है, उसने गहरी असुरक्षा से भरकर ही पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया। इस लिहाज से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता, इस क्षेत्र के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इसमें तय किया गया है कि यदि किसी बाहरी देश ने एक पक्ष पर आक्रमण किया तो इसे दूसरे देश पर भी आक्रमण माना जाएगा। सऊदी अरब पाकिस्तान के न्यूक्लियर एम्ब्रेला के अंदर है, यानी पाकिस्तान द्वारा सऊदी के रक्षा कवच के रूप में न्यूक्लियर क्षमताएं शामिल हो सकती हैं। आज की तारीख में सऊदी अरब के पास पाकिस्तान का न्यूक्लियर कवच मौजूद होगा, जो उसे किसी भी देश के हमले में बचाने में काम आ सकता है। पाकिस्तान का भी कद बड़ गया और उसे न्यूक्लियर पॉवर होने का लाभ भी मिला।

हालांकि, यह कहना अभी दूर की कौड़ी होगी कि इससे क्या पश्चिम एशिया में अमेरिकी पकड़ ढीली होगी, क्योंकि बड़ा प्लेयर अभी भी अमेरिका ही है। लेकिन अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती जरूर मिल रही है। जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र परिषद में गाजा में सीजफायर के प्रस्ताव पर भी अमेरिका अलग-थलग पड़ गया था। भारत में शंघाई सहयोग संगठन के प्रस्ताव के बाद यहां भी सीजफायर यानी गाजा में युद्ध विराम के पक्ष में अपना मत दिया था।

वैसे यह याद रखना भी जरूरी है कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच यह समझौता भारत के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। इसकी वजह साफ है कि यह समझौता पाकिस्तान को सऊदी अरब जैसे शक्तिशाली राज्य के साथ एक पारंपरिक रक्षा साथ जोड़ता है। इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है। भारत को पश्चिमी एशिया और दक्षिण एशिया में अपनी रणनीतिक पहुंच और साझेदारियों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। अगर पाकिस्तान वास्तव में सऊदी को न्यूक्लियर एम्ब्रेला प्रदान करता है तो भारत के परमाणु रणनीतिक पर यह एक नया तत्व जोड़ता है। भारत को यह देखना होगा कि इस तरह की स्थिति में कौन-सी कार्रवाई और सुरक्षा नीति अपनानी है। वैसे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इसे 'रक्षात्मक व्यवस्था' बताया है।

साथ ही साथ, यह भी ध्यान देना चाहिए कि भारत और सऊदी अरब के बीच ऊर्जा, निवेश, व्यापार आदि मामलों में बेहद मजबूत संबंध हैं। वैसे भी इस तरह के रक्षा समझौते अक्सर यह संकेत देते हैं कि भविष्य में यदि कोई संघर्ष हो, तो इसमें शामिल देशों की भूमिका और प्रतिक्रिया अधिक व्यापक हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब से खासे घनिष्ठ संबंध हैं और भारत के उद्योगपतियों के लिए भी सऊदी से दोस्ती बहुत जरूरी है।

विश्व कूटनीति में यह दौर बहुत दिलचस्प है क्योंकि इस समय कोई देश भी ये दावा करने की स्थिति में नहीं है कि वह अमेरिका का स्थायी दोस्त है। कब ट्रंप उस देश के खिलाफ मोर्चा खोल दे, यह किसी को पता नहीं। लिहाजा सारे देश अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखकर ही दूसरे देशों से संबंध व नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां विश्व स्तर पर नये गठबंधन, सत्ता समीकरण को जन्म दे रही हैं। हर देश इस समय अपने को केंद्र में रखकर कई स्तरों में वार्ता व समझौते कर रहा है। एक तरह की बार्गेनिंग या डील करने-कराने का दौर शुरू हो चुका है। इसमें पश्चिम एशिया, एशिया व ब्रिक्स के देशों के बीच भी जो संवाद स्थापित हो रहे हैं—वे यथास्थिति को तोड़ने वाले साबित हो सकते हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका के बहुत बड़े हित हैं। तेल का अकूत भंडार होने के साथ-साथ उसके शक्तिशाली सैन्य बेस उसे दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की शक्ति प्रदान करते हैं। अमेरिका के घरेलू संकट को हल करने के लिए भले ही ट्रंप कभी टैरिफ का डंडा चलाते हैं, कभी धमकियों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन दुनिया के बाकी देश भी झुक नहीं रहे है। यह एक बदलाव का द्योतक है।

प्रेरणा

ईमानदारी और सादगी की अमूल्य प्रेरणा

स्वतंत्र भारत के लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल का जीवन जितना संघर्षपूर्ण और प्रेरक था, उतना ही उनका पारिवारिक जीवन भी सादगी और ईमानदारी की मिसाल रहा। उन्होंने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का जो महान कार्य किया, उसकी गूंज आज भी हर भारतीय के मन में श्रद्धा पैदा करती है। लेकिन उनकी सच्चाई और सादगी केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उनके परिवार के जीवन में भी गहराई से दिखाई देती थी।

एक बार जब सरदार पटेल वृद्धावस्था में गंभीर रूप से बीमार हो गए, तब उनकी बेटी मणिबेन दिन-रात उनकी सेवा में लगी रहती थीं। वे पिता की देखभाल में तन-मन से जुटी हुई थीं। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी महावीर त्यागी उनसे मिलने आए। वे जब सरदार पटेल का हाल-चाल पूछने पहुंचे तो उनकी नजर मणिबेन पर पड़ी। मणिबेन की धोती में कई जगह पैबंद लगे थे। यह दृश्य देखकर त्यागी जी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके सामने वही बेटी खड़ी थी जो उस महापुरुष की संतान थी जिसने विभाजित भारत को अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और अद्भुत संगठन कौशल से एक सूत्र में पिरो दिया था। त्यागी जी अपने मन का भाव छिपा न सके और मणिबेन से बोले, "मणि! तुम उस महान व्यक्ति की बेटी हो जिसने इस देश को

एकता और अखंडता का प्रतीक बना दिया। उस लौहपुरुष की संतान होकर भी तुम पैबंद लगी धोती पहने हुए हो। क्या तुम्हें इसमें कोई संकोच नहीं होता? क्या तुम्हें यह ठीक लगता है कि इस तरह का जीवन जिया जाए?"

मणिबेन ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, "शर्म उन्हें आनी चाहिए जो झूठ और बेईमानी से जीवन जीते हैं। मैं ऐसे पिता की बेटी हूं जिन्होंने हमेशा सादगी और ईमानदारी का मार्ग अपनाया। हमारे पास साधन सीमित हैं, लेकिन यही हमारी सच्ची पूंजी है। मैं चाहती हूं कि मेरा जीवन भी उन्हीं मूल्यों पर आधारित हो, जिन पर मेरे पिता ने अपना पूरा जीवन खड़ा किया। बेईमानी और दिखावे से जीना कोई सम्मान नहीं है। सच्चा सम्मान तो ईमानदारी, नैतिकता और सादगी में ही है।"

मणिबेन का यह उत्तर सुनकर महावीर त्यागी कुछ क्षण के लिए मौन रह गए। उनके मन में गहरी श्रद्धा और सम्मान की भावना उमड़ आई। यह केवल एक बेटी का उत्तर नहीं था, बल्कि उस युग की आत्मा का साक्षात्कार था जिसमें सच्चाई, त्याग और नैतिकता ही सर्वोच्च मूल्य थे।

यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि महानता केवल पद, शक्ति या संपत्ति से नहीं आती, बल्कि मूल्यों और सिद्धांतों से आती है। सरदार पटेल ने जिस ईमानदारी और सादगी से अपना जीवन जिया, वही उनकी संतान में भी प्रतिबिंबित हुआ। मणिबेन का जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि इंसान सच्चाई और ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलता है तो उसका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। यह कथा हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो जीवन की कठिनाइयों में नैतिकता और ईमानदारी से समझौता करने लगता है। सादगी और ईमानदारी भले ही बाहरी रूप से साधारण लगे, लेकिन यही वे गुण हैं जो किसी भी इंसान को सच्चे अर्थों में महान बनाते हैं।

स्वदेशी एवं स्वावलम्बन ही नये भारत का आधार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना महोत्सव यानी प्रत्येक वर्ष विजयदशमी के अवसर पर संघ प्रमुख का उद्बोधन एक नए संदेश और नये दृष्टिकोण के साथ सामने आता है, इस उद्बोधन का पूरा राष्ट्र इंतजार करता है। इस बार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई ऐसी बातें कहीं, जो सरकार के साथ समाज के लोगों का ध्यान खींचने वाली हैं। इस पर आश्चर्य नहीं कि उन्होंने अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भारत पर थोपे गए टैरिफ की चर्चा की। 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ ने भारत के समक्ष जो कठिन चुनौती खड़ी कर दी है, उसका प्रभावी ढंग से सामना स्वदेशी और स्वावलंबन की राह पर चलकर ही किया जा सकता है। भागवत ने संबोधन में स्वदेशी और स्वावलंबन को नए भारत का आधार बताया है। उन्होंने कहा कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में परस्पर निर्भरता एक स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन यह निर्भरता कभी भी बंधन या मजबूरी में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा ताकि विदेशी निर्णयों और नीतियों पर हमारी नियंत्रण क्षमता सीमित न हो जाए। उनका कहना था कि स्वदेशी का अर्थ यह नहीं है कि हम दुनिया से कट जाएं, बल्कि यह है कि हम अपनी शर्तों पर और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संबंध बनाएं।

संघ की स्थापना का यह अवसर केवल एक उत्सव मात्र नहीं था, बल्कि यह आयोजन भारत की आत्मा और उसके भविष्य की एक गहन घोषणा थी। भागवत ने स्पष्टता और गंभीरता से अपने विचार रखे, भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में एक नया क्षितिज भी उद्घाटित किया। यह आयोजन संघ के सौ वर्ष सम्पूर्णता की साधना का मूल्यांकन ही नहीं, बल्कि आने वाले सौ वर्षों की दिशा का भी उद्घोष था। नई इबारत लिखते हुए भागवत ने स्पष्ट कहा कि संघ की कार्यप्रणाली का सार है, नए मनुष्य एवं सशक्त-स्वावलम्बी भारत का निर्माण। यह विचार सुनने में सरल लग सकता है, किंतु इसके निहितार्थ अत्यंत गहरे हैं। समाज और राष्ट्र की सारी समस्याओं का मूल व्यक्ति के भीतर छिपा है। इसीलिये देश के सभी वर्गों को एकसूत्र में जोड़ने के संकल्प के साथ संघ आगे बढ़ेगा क्योंकि जब तक व्यक्ति का चरित्र, दृष्टि और आचरण नहीं बदलते, तब तक कोई भी व्यवस्था स्थायी रूप से परिवर्तित नहीं हो सकती। संघ व्यक्ति-निर्माण के माध्यम से समाज और राष्ट्र को बदलने की दीर्घकालिक साधना कर रहा है। यही कारण है कि संघ के कार्य का परिणाम केवल शाखाओं या कार्यक्रमों में नहीं मापा जा सकता, बल्कि उस अदृश्य लेकिन ठोस नैतिक शक्ति एवं सशक्त राष्ट्रीय भावना में देखा जा सकता है, जो धीरे-धीरे समाज की दिशा बदल रही है।

भागवत ने स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक दृष्टि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और जीवन मूल्यों से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने विविधता को भारत की विशेषता बताया और समाज में विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर चेताया। उन्होंने पंच परिवर्तन की संकल्पना भी प्रस्तुत की जिसमें आत्मजागरूकता, पारिवारिक मूल्य, नागरिक अनुशासन और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को जोड़ा गया है। इस संदेश के सकारात्मक पक्ष अनेक हैं। यदि इसे गंभीरता से अपनाया जाए तो यह देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को नई दिशा दे सकता है। स्थानीय उद्योगों, हस्तशिल्प और कृषि को बढ़ावा देने से रोजगार का सृजन होगा और आर्थिक आत्मसम्मान मजबूत होगा। स्वदेशी पर बल देने से विदेशी निर्भरता घटेगी और देश की सुरक्षा व नीति संबंधी स्वतंत्रता बढ़ेगी। यदि समाज के स्तर पर भी इस सोच को अपनाया जाए तो उपभोक्तावाद के स्थान पर संवेदनशीलता और सेवा भाव विकसित होगा। विविधता के सम्मान और सामाजिक सद्भाव के आग्रह से राष्ट्र अधिक एकजुट और शक्तिशाली बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस आत्मनिर्भर भारत का आह्वान कर रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य केवल आर्थिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। यह संदेश देश की घरेलू क्षमताओं को सशक्त बनाने, आयात पर निर्भरता घटाने और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ विकास की दिशा को व्यापक सामाजिक सरोकारों से भी जोड़ता है, जिसमें महात्मा गांधी की 'स्वदेशी अपनाओ' और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 'अंत्योदय' की परिकल्पना स्पष्ट तौर पर समाहित है।

स्वदेशी और स्वावलंबन की राह पर चलकर ही नया भारत-सशक्त भारत का निर्माण किया जा सकता है। इस बात को सरकार भी रेखांकित कर चुकी है और अब संघ प्रमुख ने भी दोहरा दिया। यह समय की मांग है कि स्वदेशी और स्वावलंबन पर तब तक बल दिया जाए, जब तक वांछित सफलता न मिल जाए। जहां सरकार को स्वदेशी की राह को आसान करना होगा, वहीं समाज को सहयोग देने के लिए तत्पर रहना होगा। इस उम्मीद में नहीं रहा जाना चाहिए कि अमेरिका के साथ शीघ्र ही आपसी व्यापार समझौता हो जाएगा। एक तो जब तक ऐसा हो न जाए तब तक चैन से नहीं बैठा जा सकता और दूसरे, यदि ऐसा हो जाए तो भी भारत को स्वदेशी और स्वावलंबन की राह पर चलना छोड़ना नहीं चाहिए। व्यापारिक साझेदारों पर निर्भरता लाचारी में नहीं बदलनी चाहिए। वास्तव में इस स्थिति से बचने का ही उपाय है स्वदेशी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना। परंतु इस संदेश के साथ कई चुनौतियां और सीमाएं भी जुड़ी हुई हैं। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था इतनी आपस में गुँथी हुई है कि किसी भी देश का पूर्ण स्वावलंबन व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। अनेक तकनीकें और कच्चे माल अब भी हमें विदेशों से ही प्राप्त करने होते हैं। यदि स्वदेशी को बढ़ावा देने के नाम पर विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध या अधिक शुल्क लगाए जाते हैं तो यह व्यापार युद्ध और आर्थिक तनाव को जन्म दे सकता है।

अभियान

श्रीराम जन्म का दिव्य रहस्य और जय-विजय की

भगवान शंकर जब माता पार्वती को श्रीराम जन्म का प्रसंग सुनाने लगे तो उनके मुख से जो कथा निकली वह दिव्य भी थी और गहन रहस्यों से भरी हुई भी। उन्होंने कहा कि श्रीराम का अवतार किसी एक कारण से नहीं हुआ। ईश्वर जब अवतार लेते हैं तो उसके पीछे अनेक अद्भुत कारण होते हैं जिन्हें मनुष्य बुद्धि से पूरी तरह समझ पाना असंभव है। रामावतार भी एक गूढ़ लीला का परिणाम था।

महादेव बोले—हे भवानी! मैं राम जन्म के सभी कारणों का गान करने में असमर्थ हूँ। क्योंकि उनकी लीला अपार और अगम्य है। किंतु तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं उनके जन्म से जुड़े कुछ विशेष कारण अवश्य कहूँगा।

सबसे पहले महादेव ने जय और विजय की कथा सुनाई। ये दोनों भगवान विष्णु के परम प्रिय द्वारपाल थे। वैकुण्ठ धाम के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर ये सोचते थे कि वे स्वयं भी प्रभु के समान महत्त्वपूर्ण हैं। धीरे-धीरे उनके हृदय में यह अहंकार घर करने लगा कि वे जिसे चाहें, उसे भगवान विष्णु के दर्शन से रोक सकते हैं।

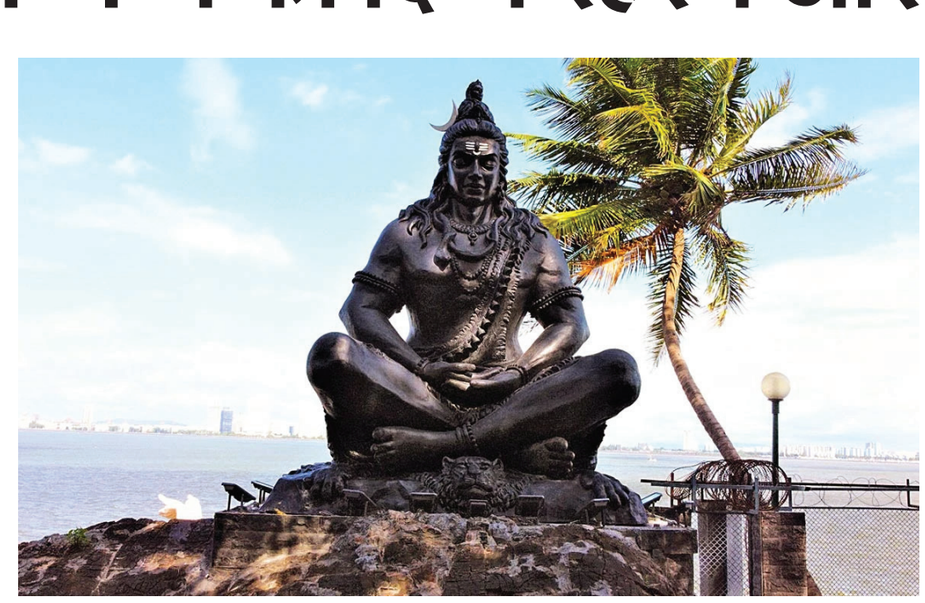

एक दिन सनक, सनंदन, सनातन और सनत्कुमार—ये चारों ब्रह्मा के मानस पुत्र, प्रभु दर्शन की उत्कट इच्छा लेकर वैकुण्ठ में प्रवेश करने पहुँचे। वे अत्यंत निरहंकारी और प्रभु-प्रेम में लीन थे। इस कारण वे यह भूल ही गए कि द्वार पर कोई रक्षक भी खड़ा है। वे सीधे भीतर जाने लगे।

जय और विजय ने जब यह दृश्य देखा तो उनका अहंकार भड़क उठा। उन्हें लगा कि इन ऋषियों ने उनका अपमान किया है। उन्होंने क्रोध में आकर सनकादि ऋषियों को अपशब्द कहे और भीतर प्रवेश करने से रोका।

सनकादि ऋषियों का मन तो समुद्र की तरह शांत था। वे अपशब्दों से विचलित नहीं हुए। किंतु उन्होंने जब देखा कि इन दोनों द्वारपालों के भीतर अहंकार और दुष्टता कूट-कूट कर भरी हुई है, तब उन्होंने गंभीर स्वर में कहा—"तुम दोनों वास्तव में राक्षसी प्रवृत्ति के हो, अतः अगले जन्म में राक्षस बनकर पृथ्वी पर जन्म लो।"

श्राप मिलते ही जय और विजय के होश उड़ गए। वे रोते-बिलखते भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और क्षमा माँगने लगे। उस समय स्वयं भगवान प्रकट हुए और बोले—"ऋषियों के वचन अटल हैं। यह श्राप अवश्य फलीभूत होगा। किंतु मेरे सेवक होने के कारण मैं तुम्हें वर देता हूँ कि जब-जब तुम राक्षस बनकर जन्म लोगे, तब-तब मेरे ही हाथों से मोक्ष को प्राप्त करोगे।"

भगवान विष्णु के वचनों ने उन्हें सांत्वना दी। अब यह निश्चित हो गया कि जय और विजय तीन बार राक्षस रूप में जन्म लेंगे और हर बार भगवान स्वयं अवतार लेकर उनका उद्धार करेंगे।

पहली बार वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में पैदा हुए। उस समय भगवान विष्णु ने वराह और नरसिंह अवतार लेकर उनका वध किया। दूसरी बार वे रावण और कुम्भकर्ण के रूप में जन्मे और तब भगवान ने श्रीराम के रूप में अवतार लेकर इस त्रैलोक्य को उनके आतंक से मुक्त किया। तीसरी और अंतिम बार वे शिशुपाल और दंतवक्र बने और श्रीकृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। रामावतार का रहस्य यहीं से जुड़ता है। जब जय और विजय ने रावण और कुम्भकर्ण का रूप लिया, तब उनके अहंकार और दुष्टता से सम्पूर्ण सृष्टि त्रस्त हो गई। देवता और ऋषि तक उनके अत्याचार से भयभीत थे। पृथ्वी माता स्वयं करुणा से भरकर भगवान से प्रार्थना करने लगीं कि वे धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए अवतार लें।

इसीलिए भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में अवतार लिया। रामावतार केवल रावण के वध के लिए नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना, आदर्श मर्यादा का प्रदर्शन, सत्य और प्रेम की रक्षा तथा भक्तों को सुरक्षा देने के लिए था।

महादेव माता पार्वती से कहते हैं—ईश्वर की लीला का रहस्य गहन है। एक ओर यह ऋषियों के श्राप और जय-विजय के अहंकार से जुड़ा है, तो दूसरी ओर भक्तों की पुकार और सृष्टि की रक्षा से। श्रीराम के जन्म की यह कथा वास्तव में यह सिखाती है कि अहंकार चाहे देवता के हृदय में ही क्यों न आ जाए, अंततः वह पतन का कारण बनता है। और जब-जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब-तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा और धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेते हैं।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

ठाणे में 530 लिपिक-टाइपिस्टों की अनुकंपा नियुक्ति, जिलाधिकारी ने ईमानदारी और जिम्मेदारी का संदेश दिया

ठाणे। ठाणे ज़िले में अनुकंपा के आधार पर 530 लिपिक-टाइपिस्टों की नियुक्ति का ऐतिहासिक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे जनता के प्रति ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करें और महाराष्ट्र को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के सपने में योगदान दें। यह समारोह ज़िला योजना समिति हॉल में हुआ, जिसमें अनुकंपा और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

समारोह में विधायक संजय केलकर, विधायक सुलभा गायकवाड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, अतिरिक्त आदिवासी विकास परियोजना आयुक्त गोपीचंद कदम, पुलिस अधीक्षक डॉ. डी. स्वामी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और नवनियुक्त उम्मीदवार उपस्थित थे। समारोह का मुंबई के यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में आयोजित मुख्य राज्य रोजगार मेले से भी सीधा प्रसारण किया गया।

जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने बताया कि अनुकंपा के तहत यह निर्णय 45 सरकारी मामलों पर विचार करने के बाद लिया गया। दस्तावेज़ सत्यापन जैसी जटिल प्रक्रिया केवल दो से ढाई महीने में पूरी की गई। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग और मार्गदर्शन सत्रों के माध्यम से उम्मीदवारों को पूरी जानकारी दी गई, ताकि वे अपने नए पद की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और लगन से निभा सकें।

राज्य में एक ही दिन में इतने उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान करना एक रिकॉर्ड जैसा रहा। ठाणे ज़िला नियोजन भवन में ग्रुप सी में 98, ग्रुप डी में 159 और लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 273 उम्मीदवारों को कुल 530 नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इससे दिवंगत अधिकारियों के परिवारों को भी राहत मिली।

समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान और राज्यगान से हुई। इसे सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय की स्थापना शाखा के अधिकारी और कर्मचारी दिन-रात लगे रहे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, पुलिस अधीक्षक डॉ. डी. स्वामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिश्चंद्र पाटिल और अन्य अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने में अहम योगदान दिया।

जिलाधिकारी ने उम्मीदवारों को याद दिलाया कि यह नियुक्ति सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि राज्य और जनता की सेवा का अवसर है। उन्होंने कहा कि मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करने वाले कर्मचारी ही समाज में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारी और कार्यकर्ता इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की सफलता में शामिल रहे और नवनियुक्त कर्मचारियों के भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं।

इस कार्यक्रम ने यह भी दिखाया कि राज्य सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से योग्य और जरूरतमंद लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में कितनी सक्रिय है। आगामी समय में यह नियुक्ति महाराष्ट्र प्रशासन में नयी ऊर्जा और दक्षता लाने का अवसर साबित होगी।

फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में भीषण विस्फोट, दो बच्चों की मौत, आठ गंभीर घायल

फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद जिले के कादरी गेट थाना क्षेत्र में शनिवार को सातनपुर मंडी के पास संचालित एक कोचिंग सेंटर में अचानक भीषण विस्फोट हो गया। इस हादसे में कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे करीब दस बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि एक किलोमीटर दूर तक कई मकान हिल गए।

विस्फोट से कोचिंग सेंटर का पूरा स्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया। अंदर की स्लैब और पक्की दीवारें बाहर उछल कर 50 मीटर दूर तक जा गिरीं, वहीं लोहे की जाली डेढ़ सौ मीटर दूर पानी के गड्ढे में फेंक दी गई। इस हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ छात्रों के शरीर के मांस के लोथड़े घटना स्थल पर ही पड़े मिले। विस्फोट की वजह से आसपास खड़ी मोटरसाइकिलें, स्कूटी और साइकिल जैसे वाहन भी 50 मीटर दूर तक उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और फतेहगढ़ व कादरी गेट थाना पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल भी घटना स्थल पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई।

पुलिस ने कोचिंग सेंटर में मौजूद एक शिक्षक को हिरासत में ले लिया है और विस्फोट के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि विस्फोट किसी विस्फोटक या रासायनिक पदार्थ के कारण हुआ हो सकता है, लेकिन सटीक कारणों का पता पोस्टमार्टम और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के बाद ही चलेगा। हादसे के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है। घायल बच्चों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस और प्रशासन ने परिवारों को घटनास्थल पर आने से रोकते हुए राहत और बचाव कार्यों में तेजी ला दी है।

फर्रुखाबाद के लोगों में इस हादसे को लेकर गहरा शोक और भय व्याप्त है। प्रशासन ने सभी स्कूल और कोचिंग सेंटरों को सुरक्षा नियमों के कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी शुरू कर दी है। इस भयानक हादसे ने जिले के निवासियों को झकझोर कर रख दिया है और पूरे जिले में सुरक्षा के मानकों की समीक्षा की आवश्यकता को उजागर कर दिया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और गुजरात के वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई की उपस्थिति में राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान- 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' का गांधीनगर में शुभारंभ

गुजरात से शुरू किया गया यह राष्ट्रव्यापी अभियान देश के छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए आर्थिक रूप से वरदान साबित होगा : श्री कनुभाई देसाई, वित्त मंत्री, गुजरात

केंद्रीय वित्त मंत्री सहित महानुभावों के करकमलों द्वारा लाभार्थियों को उनके रुपए वापस किए गए

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण :-

- इस अभियान के जरिए नागरिकों द्वारा बचाए गए प्रत्येक रुपए को उन्हें या उनके परिवार को वापस किया जाएगा
- केवाईसी और री-केवाईसी अभियान में प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों, विशेषकर गुजरात ग्रामीण बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की सक्रिय भूमिका

गांधीनगर : केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और गुजरात के वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई की उपस्थिति में शनिवार को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' शीर्षक के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इस अवसर पर गांधीनगर लोकसभा के सांसद और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अभियान की सफलता के लिए शुभकामना संदेश प्रेषित किया।

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अभियान एक सरल, लेकिन शक्तिशाली संदेश देता है कि नागरिकों द्वारा बचाया गया प्रत्येक रुपया उन्हें या उनके परिवार को वापस करना चाहिए। बिना दावे वाली बैंक जमा राशि (डिपॉजिट्स), बीमा पॉलिसी की आय, लाभांश, म्यूचुअल फंड आय और पेंशन केवल कागज पर दर्ज एंट्रियां नहीं है, बल्कि वह सामान्य परिवारों की मेहनत से कमाई हुई बहुमूल्य पूंजी-बचत है। यह बचत शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाएगी।

उन्होंने कहा कि 31 अगस्त, 2025 तक विभिन्न बैंकों ने लगभग 75 हजार करोड़ रुपए से अधिक की बिना दावे वाली जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को हस्तांतरित की है। इसके अलावा, आरबीआई के पास बीमा क्षेत्र में लगभग 14 हजार करोड़ रुपए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में 3 हजार करोड़ रुपए, कंपनियों में 9 हजार करोड़ रुपए और 19 हजार करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बिना दावे के पड़े हैं। इस प्रकार, देश में कुल 1.82 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय संपत्तियां बिना दावे के पड़ी हैं, यदि यह राशि वापस लौटाई जाए तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ा फायदा होगा।

वित्त मंत्री ने इस अभियान के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में तीन 'ए' – जागरूकता, पहुंच और कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया। जागरूकता का उद्देश्य नागरिक और समुदाय को बिना दावे वाली संपत्तियों का पता लगाने के तरीके के बारे में सूचित करना है। जबकि पहुंच का उद्देश्य सरल डिजिटल उपकरणों और जिला स्तरीय पहुंच प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना है। वहीं, कार्रवाई का उद्देश्य समयबद्ध और पारदर्शी दावे के निपटान पर जोर देना है। ये तीनों स्तंभ साथ मिलकर नागरिकों और वित्तीय संस्थानों के बीच की खाई को पाटने में मदद करेंगे, समुदाय जागरूकता को बढ़ावा देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और आसानी के साथ अपनी सही बचत वापस प्राप्त कर सके।

वित्त मंत्री ने हाल ही के केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) और री-केवाईसी (पुनः केवाईसी) अभियान में प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों, विशेषकर गुजरात ग्रामीण बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों की सक्रिय भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि इन प्रयासों ने नागरिकों और औपचारिक वित्तीय व्यवस्था के बीच के जुड़ाव को मजबूत बनाया है। गांवों और नगरों में शुरू किए गए इन प्रयासों से यह सुनिश्चित हुआ है कि लाभार्थी अपनी बचत और अधिकार के साथ जुड़े रहते हैं, जो वर्तमान अभियान की सफलता के लिए एक मजबूत आधार साबित होगा। वित्त मंत्री ने सभी संस्थानों से अनुरोध किया कि वे इस राष्ट्रव्यापी पहल के दौरान दावा न की गई वित्तीय संपत्तियों को लेकर समान समर्पण दिखाएं और पहुंच बढ़ाएं ताकि कोई भी नागरिक अपने हक के पैसे से वंचित न रहे।

उन्होंने कहा कि यह अभियान जन धन योजना और यूपीआई से लेकर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तक, वित्तीय समावेश में भारत की व्यापक उपलब्धियों पर आधारित है ताकि नागरिक न केवल वित्तीय सेवाएं ही नहीं, बल्कि जिसके हकदार हैं, उसे भी वापस प्राप्त कर सकें। व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक यानी तीन महीनों के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। डिजिटल प्रदर्शनी और हेल्प डेस्क नागरिकों को उनकी बिना दावे की वित्तीय संपत्तियों का आसानी से पता लगाने और उसका दावा करने में मदद करेंगे, जो नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता और जीवन को आसान बनाने के उनके व्यापक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है।

गुजरात के वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात से शुरू किए गए इस राष्ट्रव्यापी अभियान- 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' देश के छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए आर्थिक रूप से वरदान साबित होगा। इस अभियान के जरिए बैंक के बचत खाते में, बीमा कंपनियों में, म्यूचुअल फंड और पेंशन जैसे क्षेत्रों में वर्षों से बिना दावे के पड़े उनके रुपए उन्हें सम्मान के साथ वापस मिल रहे हैं। यह रुपए उनके परिवार में शिक्षा और स्वास्थ्य सहित अन्य विकास कार्यों के लिए उपयोगी होंगे, जिसके चलते ऐसे परिवारों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय बदलाव आएगा।

वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने कहा कि गुजरात में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लगभग 2500 करोड़ रुपए तथा बीमा कंपनियों में लगभग 235 करोड़ रुपए की बिना दावे वाली राशि पड़ी है, जो इस अभियान के माध्यम से उनके असली मालिकों को वापस की जाएगी। गुजरात सरकार के सभी विभागों में इस प्रकार की रकम के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाकर संबंधित लोगों के घर तक उनके अधिकार की राशि पहुंचाई जाएगी।

श्री देसाई ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले से देशवासियों को विश्वास दिलाया था कि जीएसटी टैक्स में बड़ी राहत दी जाएगी, जिसका केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के सक्रिय प्रयासों से नवरात्रि के पहले दिन से देश भर में क्रियान्वयन शुरू हो गया है। इसके परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री के मंत्र 'ईज ऑफ लिविंग' को बल मिला है। इतना ही नहीं, आम नागरिकों को भी इसका सर्वाधिक लाभ मिला है। गुजरात में पिछले 10 वर्षों के मुकाबले इस वर्ष नए वाहनों की बिक्री 10 गुना अधिक हुई है। उन्होंने इस राष्ट्रव्यापी अभियान के लिए गुजरात का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का गुजरात सरकार की ओर से आभार व्यक्त किया।

वित्तीय क्षेत्र में बिना दावे की संपत्तियों के कुशल और त्वरित समाधान की सुविधा के लिए इस अभियान में उपस्थित महानुभावों ने विभिन्न बैंकों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी स्टॉलों का दौरा कर जानकारी हासिल की।

केंद्रीय वित्त मंत्री सहित महानुभावों के करकमलों द्वारा म्यूचुएल फंड, कॉर्पोरेट फंड, बीमा, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत विभिन्न लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री ने अभियान की मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का विमोचन किया।

समारोह में केंद्रीय वित्त विभाग के सचिव श्री एम. नागराजू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मदी के नेतृत्व और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के मार्गदर्शन में 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत गुजरात से की जा रही है। आज केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में जन धन योजना, यूपीआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाने पर लगातार ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके भाग के रूप में, वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक बुनियादी ढांचा सुविधाओं से लेकर बैंकिंग और शासन में सुधारों के साथ-साथ देश में समावेशी वित्तीय व्यवस्था की एक मजबूत नींव रखी गई है।

इस अवसर पर केंद्रीय वित्त विभाग के संयुक्त सचिव श्री आशीष मोरे ने स्वागत भाषण में कहा कि गुजरात से शुरू हुआ यह राष्ट्रीय अभियान सरकार, संस्थानों और नागरिकों को जोड़ने वाला अभियान है। इसके जरिए नागरिकों की मेहनत की कमाई की बचत और पूंजी का प्रत्येक भाग उन्हें या उनके परिवार तक सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस अभियान के अंतर्गत बैंक में जमा राशि, बीमा दावे, म्यूचुअल फंड, लाभांश और पेंशन के रूप में जो बड़ी धनराशि बिना दावे के पड़ी है, उसे नागरिकों तक तेज, पारदर्शी और सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस अभियान को केवल सामान्य प्रशासनिक कार्य के रूप में नहीं, बल्कि जनजागरूकता अभियान के रूप में आगे बढ़ा रही है।

बैंक ऑफ बड़ौदा, अहमदाबाद जोन के महाप्रबंधक और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) गुजरात के संयोजक श्री अश्विनी कुमार ने आभार व्यक्त किया।

समारोह में राज्य के वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉ. टी. नटराजन, वित्त विभाग की सचिव श्रीमती आरती कंवर, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विक्रांत पांडे, केंद्र और राज्य सरकार के उच्च अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा), पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), संबंधित बैंक और बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड और पेंशन संस्थानों जैसे विभिन्न वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित कई लाभार्थी उपस्थित रहे।

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा समन्वित यह अभियान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) बैंक और बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड और पेंशन संस्थानों के साथ एक सामान्य प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है।

6 से 9 अक्टूबर तक गोझरिया स्थित रेलवे फाटक नं. 78 बंद रहेगा

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर महेसाणा-गोझरिया हाईवे के बीच गोझरिया स्थित रेलवे फाटक नं. 78 आंबलियासन-विजापुर रेलवे लाइन गेज परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत चेक रेल एवं रोड अलाइनमेंट पर डामर कार्य के चलते 6 अक्टूबर 2025 से 9 अक्टूबर 2025 तक (4 दिन) बंद रहेगा। सड़क उपयोगकर्ता इस अवधि के दौरान गांधीनगर-गोझरिया-विसनगर हाईवे स्थित रेलवे फाटक नं. 77 से आवागमन कर सकते हैं।

25,000 से $21 बिलियन साम्राज्य तक: वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में टॉरेंट ग्रुप संस्थापक स्व. श्री यू.एन. मेहता की प्रेरणादायक यात्रा का उत्सव

- **स्व. श्री यू.एन. मेहता: भारत में फार्मा और पावर सेक्टर के अग्रणी, जिन्होंने बनाया एक कॉर्पोरेट दिग्गज और एक अमूल्य उदारवादी विरासत**
- **वीजीआरसी नॉर्थ गुजरात में सम्मान: स्व. श्री यू.एन. मेहता जैसे दूरदर्शी उद्यमियों को सलाम, जिन्होंने बदल दी भारत की उद्योग और विकास की कहानी**

गांधीनगर : गुजरात की पवित्र धरती ने अनेक विभूतियों को जन्म दिया है, जिन्होंने भारत की प्रगति की दिशा तय की। इन्हीं में से एक हैं श्री उत्तमभाई नथालाल मेहता (14 जनवरी, 1924 – 31 मार्च, 1998) जो टॉरेंट ग्रुप के संस्थापक और भारतीय उद्योग जगत के उज्ज्वल चमकता सितारा हैं। उन्होंने उस समय दवाओं का उत्पादन शुरू किया, जब भारत जीवनरक्षक दवाओं के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर था। केवल यही नहीं, बिजली उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में भी उन्होंने वैश्विक मानकों वाली परियोजनाएँ खड़ी कीं और भारत को गहरे बिजली संकट से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। श्री मेहता का जीवन गुजरात की उस उद्यमशीलता का प्रतीक है, जिसने न केवल राज्य, बल्कि पूरे देश को आत्मनिर्भरता और समृद्धि की राह दिखाई।

एक सामान्य युवक से उद्योग जगत में चमकता सितारा बनने की कहानी

उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले के छोटे से गाँव मेमदपुर में जन्मे श्री यू.एन. मेहता का जीवन इसी भावना का जीवंत उदाहरण है। अत्यंत साधारण परिवार में जन्मे और मात्र दो वर्ष की आयु में माता का साया खो देने वाले इस बालक ने कभी हार नहीं मानी। संघर्षों के बीच उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई का रुख किया। वहाँ विल्सन कॉलेज से केमिस्ट्री में स्नातक की डिग्री प्राप्त की जो उनकी आगे की औद्योगिक यात्रा के लिए मजबूत नींव साबित हुई।

परिस्थितियाँ कठिन थीं, लेकिन हौसले भी बुलंद थे। आर्थिक अभावों के चलते उच्च शिक्षा का उनका सपना अधूरा रह गया, फिर भी उन्होंने 1944 में सरकारी नौकरी कर अपने जीवन की नई शुरुआत की। जल्द ही उन्होंने 1945 से 1958 तक स्विस फार्मा कंपनी 'सैंडोज़' में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य किया। यहीं से उन्होंने औषधि उद्योग की बारीकियाँ सीखी और एक दिन अपना कुछ करने का स्वप्न देखा।

साहस, संकल्प और दूरदर्शिता से उद्योग जगत में हुए प्रसिद्ध श्री यू.एन. मेहता

1959 में श्री यू.एन. मेहता ने साहस और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए मात्र 25,000 रुपये की पूँजी से अहमदाबाद में 'ट्रिनिटी लेबोरेट्रीज़' (अब टॉरेंट फार्मा) की स्थापना की। यह उस दौर की बात है जब भारत विदेशी दवाओं पर निर्भर था और देश में फार्मा उत्पादन की कल्पना भी कठिन मानी जाती थी। लेकिन गुजरात की धरती पर जन्मे इस कर्मयोगी ने यह असंभव कार्य संभव कर दिखाया।

जीवन ने उन्हें बार-बार परखा। 39 वर्ष की आयु में दवा के दुष्प्रभाव से मानसिक बीमारी, 53 वर्ष में दुर्लभ प्रकार का कैंसर, और 62 वर्ष में हृदय रोग के कारण बाईपास सर्जरी जैसी गंभीर परिस्थितियाँ सामने आईं। उनका पहला व्यावसायिक प्रयास भी असफल रहा, और उन्हें अपने गाँव लौटना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने अटूट आत्मविश्वास के साथ वे फिर उठ खड़े हुए। 48 वर्ष की आयु में वो पुनः सफलता के शिखर तक पहुँच गए और गुजरात को दिया एक ऐसा औद्योगिक अग्रणी जिसने देश को आत्मनिर्भर औषधि निर्माण की दिशा दिखाई।

दूरदर्शिता से शुरू हुई टॉरेंट समूह की सफलता की यात्रा

1968 में जब भारत का औषधि उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नियंत्रण में था, तब श्री यू.एन. मेहता ने अपनी असाधारण दूरदृष्टि और साहस के साथ मनोचिकित्सा संबंधी दवाओं के निर्माण और विपणन की पहल की। यह कदम उस दौर में किसी भी भारतीय उद्यमी के लिए जोखिमपूर्ण था, परंतु श्री मेहता ने इसे देश की आवश्यकता और आत्मनिर्भरता के संकल्प के रूप में अपनाया। उनकी यही नवोन्मेषी सोच और "नीश मार्केटिंग" रणनीति टोरेंट समूह की सशक्त नींव बनी, जिसने आगे चलकर स्वास्थ्य, ऊर्जा और खेल जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्टता का परचम लहराया। आज टोरेंट समूह का बाज़ार मूल्य 31 मार्च 2025 तक 21.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुँच चुका है। टोरेंट समूह आज गुजरात की उस नवाचार-प्रधान औद्योगिक संस्कृति का प्रतीक है, जो परिश्रम, दृष्टि और सामाजिक उत्तरदायित्व को साथ लेकर चलती है।

सेवा को समर्पित जीवन, संस्कारों से संवरती विरासत

श्री मेहता केवल एक सफल उद्योगपति नहीं, बल्कि संवेदनशील समाजसेवी भी थे। उन्होंने जनस्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाते हुए यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर (UNMICRC) की स्थापना की, जो आज भी वंचित वर्गों को सस्ती और सुलभ हृदय चिकित्सा उपलब्ध करा रहा है। उनकी पत्नी, श्रीमती शारदाबेन मेहता ने भी बाल स्वास्थ्य और कन्या शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए समाजसेवा को नई दिशा दी और UNMICRC की स्थापना में अहम भूमिका निभाई।

उनकी चारों संताने सुधीर, समीर, मीना और नयना आज भी अपने माता-पिता के मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए, टोरेंट समूह को नई ऊँचाइयों तक ले जा रही हैं और समाजहित के कार्यों में सक्रिय योगदान दे रही हैं। उनकी जन्मशताब्दी (2024) के अवसर पर मेहता परिवार ने यू.एन.एम. फाउंडेशन के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपये स्वास्थ्य, शिक्षा, ज्ञान-विस्तार, पर्यावरण, कला-संस्कृति और सामाजिक कल्याण हेतु दान करने की भी घोषणा की।

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस बनेगा स्थानीय नेतृत्व, साझा दृष्टि और सतत प्रगति का संगम

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से गुजरात सरकार यह स्पष्ट संदेश दे रही है कि विकास केवल आर्थिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक साझा दृष्टि, ठोस योजना और सतत प्रयास का परिणाम है। इस पहल के जरिये सरकार यह प्रतिपादित कर रही है कि राज्य के हर कोने में प्रगति को सशक्त बनाने के लिए नेतृत्व, नीति और सामूहिक भागीदारी का होना अनिवार्य है। श्री यू.एन. मेहता जैसे दूरदर्शी औद्योगिक नेतृत्व इस दृष्टि के जीवंत उदाहरण हैं, जिन्होंने कठिन परिश्रम और स्पष्ट दिशा के साथ न केवल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को रूपांतरित किया, बल्कि समावेशी और सतत विकास की नई राह भी दिखाई।

पटेल ने 'गुजरात दीपोत्सवी अंक' विक्रम संवत-2081 का विमोचन किया

27 शोध लेखों, 31 लघु उपन्यासों, 17 व्यंग्य रचनाओं, 11 नाटिकाओं, 97 काव्य रचनाओं एवं मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करती 51 रंगीन तस्वीरों एवं मनमोहक चित्रों से सजा दीपोत्सवी अंक

गांधीनगर, : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को गांधीनगर में 'गुजरात दीपोत्सवी अंक' विक्रम संवत 2081 का विमोचन किया। राज्य के सूचना विभाग की ओर से प्रति वर्ष प्रकाशित किए जाने वाले दीपोत्सवी अंक की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी 'गुजरात दीपोत्सवी अंक' के माध्यम से गुजरात के साहित्य, कला, इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और संस्कार विरासत को प्रस्तुत किया गया है। दीपोत्सवी अंक के विमोचन अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव और सूचना एवं प्रसारण विभाग की सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह, सूचना निदेशक श्री के.एल. बचाणी, अपर सूचना निदेशक श्री अरविंदभाई पटेल सहित कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे।

इस वर्ष दीपोत्सवी-2081 में गुजरात के मूर्धन्य साहित्यकारों की रचनात्मक कलम के माध्यम से ऐसे चिंतनात्मक विचारों, काव्यों, लघु उपन्यासों, व्यंग्य रचनाओं और नाटिकाओं युक्त भव्य और विविध साहित्य परोसा गया है, जिसकी खूशबू से पाठक मित्रों का मन प्रफुल्लित हो जाएगा।

इतना ही नहीं, गुजरात के लब्धप्रतिष्ठित साहित्यकारों की सृजनशील कलम द्वारा लिखी गई साहित्यिक कृतियां दीपोत्सवी अंक में प्रकाशित की गई हैं। यह शानदार अंक 27 शोध लेखों, 31 लघु उपन्यासों, 17 व्यंग्य रचनाओं, 11 नाटिकाओं और 97 काव्य रचनाओं से संपन्न है। इसके साथ ही, प्रकृति, लोकजीवन और मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करती करीब 51 रंगीन तस्वीरें और मनमोहक चित्र इस अंक को और भी नयनरम्य बनाते हैं।

5 और 6 अक्टूबर को चलेगी साबरमती-गुड़गाँव और मुंबई-सेंट्रल-साबरमती वंदे भारत वन वे स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा और उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से साबरमती-गुड़गाँव और मुंबई सेंट्रल-साबरमती के बीच विशेष किराये पर वंदे भारत सुपरफास्ट वन वे स्पेशल चलाने का निर्णय लिया गया है। इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 09401 साबरमती–गुडगाँव वंदेभारत सुपरफास्ट वन-वे स्पेशल [02 फेरे]

ट्रेन संख्या 09401 साबरमती-गुडगाँव वंदेभारत स्पेशल 5 और 6 अक्टूबर 2025 को साबरमती से 17.30 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 08.25 बजे गुडगाँव पहुंचेगी।

मार्ग में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, मारवाड़ जं., अजमेर, जयपुर, अलवर और रेवाड़ी स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार श्रेणी के कोच होंगे। ट्रेन संख्या 09153 मुंबई सेंट्रल–साबरमती वंदेभारत सुपरफास्ट वन-वे स्पेशल [02 फेरे]

ट्रेन संख्या 09153 मुंबई सेंट्रल-साबरमती वंदेभारत स्पेशल 5 और 6 अक्टूबर 2025 को मुंबई सेंट्रल से 10.30 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 17.20 बजे साबरमती पहुंचेगी।

मार्ग में यह ट्रेन बोरीवली, वापी, सूरत और वडोदरा स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार श्रेणी के कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09401 और 09153 की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू हैं। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

ब्लॉक के कारण 8 और 9 अक्टूबर की पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन प्रभावित

दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल में कोलाघाट स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य हेतु 02 अक्टूबर से 12 अक्टूबर, 2025 तक विभिन्न चरणों में NI कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त 13 अक्टूबर, 2025 को 4 घंटे का पूर्ण ब्लॉक लेकर कार्य किया जाएगा। इस कार्य के चलते पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल से संचालित पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन (12905) प्रभावित होगी। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार विस्तृत विवरण इस प्रकार हैः

1. 8 अक्टूबर, 2025 को पोरबंदर से प्रस्थान करने वाली पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस (12905) अपने निर्धारित समय से 75 मिनट देरी से चलेगी।
2. 9 अक्टूबर, 2025 को पोरबंदर से प्रस्थान करने वाली पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस (12905) अपने निर्धारित समय से 3 घंटे देरी से चलेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा से पूर्व संबंधित ट्रेनों के समय की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

नांदगांव स्टेशन पर बड़े रीमॉडलिंग कार्य की शुरुआत, यात्रियों की यात्रा योजनाओं पर पड़ेगा असर

भुसावल मंडल का नांदगांव स्टेशन आने वाले दिनों में एक बड़े बदलाव से गुज़रने वाला है। जलगांव – मनमाड खंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन के साथ-साथ लंबी हॉल लूप लाइन निर्माण परियोजना के हिस्से के रूप में यहाँ यार्ड रीमॉडलिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। रेलवे ने इस कार्य के लिए विशेष ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लागू किया है, जिससे तीन दिनों तक ट्रेनों के परिचालन पर सीधा असर पड़ेगा। इस परियोजना का उद्देश्य यात्रियों की बढ़ती संख्या और मालगाड़ियों के दबाव को देखते हुए रेल यातायात को और अधिक सुरक्षित, सुगम और तेज़ बनाना है। नई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग व्यवस्था पुरानी मैन्युअल प्रणाली की जगह लेगी, जिससे ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से डिजिटल और स्वचालित नियंत्रण में आ सकेगा।

लेकिन इसके चलते 7 और 8 अक्टूबर 2025 को कई लोकल और पैसेंजर ट्रेनें पूरी तरह से रद्द रहेंगी। इनमें देवळाली – भुसावल एक्सप्रेस (11113), भुसावल – देवळाली एक्सप्रेस (11114), इगतपुरी – भुसावल मेमू (11119) और भुसावल – इगतपुरी मेमू (11120) शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों को अग्रिम चेतावनी देते हुए अपनी यात्रा योजनाएँ बदलने और वैकल्पिक गाड़ियों का विकल्प तलाशने की सलाह दी है।

इतना ही नहीं, 9 अक्टूबर 2025 को भी वही चारों ट्रेनें रद्द रहेंगी और कई लंबी दूरी की गाड़ियाँ विलंब से चलेंगी। इनमें लोकमान्य टिळक टर्मिनस – हरिद्वार एक्सप्रेस (12171) लगभग 2 घंटे 30 मिनट देरी से, लोकमान्य टिळक टर्मिनस – गोड्डा एक्सप्रेस (22312) 2 घंटे देरी से और मुंबई – लखनऊ एक्सप्रेस (12534) 2 घंटे देरी से अपने गंतव्य तक पहुँचेंगी।

रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह असुविधा केवल अस्थायी है और कार्य पूर्ण होने के बाद इस मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुचारु और सुरक्षित हो जाएगी। नांदगांव स्टेशन को एक आधुनिक स्वरूप देने की इस परियोजना से क्षेत्रीय यात्रियों के साथ-साथ माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

यानी फिलहाल यात्रियों को थोड़ी परेशानी ज़रूर झेलनी होगी, लेकिन आने वाले समय में यही असुविधा रेलवे की सुविधा और विश्वसनीयता में बदल जाएगी।

पश्चिम रेलवे
वडोदरा मंडल

को-को बोगी की मरम्मत/पुनर्वास/ओवरहालिंग

निविदा सूचना संख्या: EL/TRS/BRC/2025-26/5 दिनांक 03/10/2025

निविदासंख्या:ELSBRC2526REPREBOHBOGIE4 कार्य का नाम और स्थान: को-को बोगी WAP7/WAG9 की मरम्मत/पुनर्वास/ओवरहालिंग (विद्युत लोको शेड, वडोदरा, पश्चिम रेलवे) **कार्य की अनुमानित लागत:** ₹ 4,74,71,155.60 **जमा की जाने वाली बोली सुरक्षा:** ₹ 3,87,400/- **निविदा जमा करने और निविदा खोलने की तिथि और समय:** इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निविदा 03.11.2025 को 15:00 बजे तक जमा की जा सकती है और उसके बाद 03.11.2025 को 15:30 बजे खुलेगी। **वेबसाइट विवरण, सूचना पट्ट का स्थान जहाँ निविदा का पूरा विवरण देखा जा सकता है और कार्यालय का पता जहाँ से निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकता है:** विद्युत लोको शेड, नवा यार्ड, वडोदरा वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (टीआरएस), विद्युत लोको शेड, नवायार्ड, वडोदरा-390002गुजरात

https://www.ireps.gov.in BRC211

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

बीजेपी में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए टिकट पर मंथन, 25-30 विधायकों की कुर्सी दांव पर

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने टिकटों पर गहन मंथन शुरू कर दिया है। 4 और 5 अक्टूबर को पटना में होने वाली चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में पार्टी के बड़े नेता सीटों और संभावित उम्मीदवारों पर रायशुमारी करेंगे। बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे।

बीजेपी की वर्तमान strength 80 विधायक है, और 2025 विधानसभा चुनाव में 70 की उम्र पार कर चुके कई वरिष्ठ नेताओं की सीटें खतरे में हैं। पूर्व कृषि मंत्री और आरा से विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह 77 साल के हो चुके हैं, वहीं छपरा से विधायक डॉक्टर सीएन गुप्ता भी 78 वर्ष के हैं। 71 वर्षीय सात बार के विधायक नंदकिशोर यादव और बांका से 72 साल के राम नारायण मंडल भी आगामी टिकट के लिए समीक्षा में हैं। बड़हरा से 73 वर्षीय राघवेंद्र प्रताप सिंह और रामनगर से 71 वर्षीय भागीरथी देवी जैसे विधायक भी चुनाव समिति की तलवार की धार पर हैं।

विधायकों के प्रदर्शन पर भी गहन चर्चा की जाएगी। कई ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ एंटी-इंकंबेंसी फैक्टर है, और सर्वे में जनता में असंतोष दिखाई दे रहा है। ऐसे विधायकों में से 10-12 का टिकट कटने की संभावना है। पिछले साल विश्वास मत के दौरान बगावती तेवर दिखाने वाले विधायकों का भी राजनीतिक भविष्य समीक्षा के दायरे में है। अलीपुर से मिश्रीलाल यादव, नरकटियागंज से रश्मि वर्मा और रामनगर विधायक भागीरथी देवी जैसे नेताओं ने उस समय पार्टी के पक्ष में मतदान किया, फिर भी उनके टिकट पर सवाल उठ रहे हैं।

साथ ही पार्टी नेता पुत्रों के चुनावी भविष्य पर भी फैसला करेगी। अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत, पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के पुत्र, नंदकिशोर यादव के पुत्र और अन्य कई नेता पुत्र चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के पुत्र और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह के पुत्र भी अपनी दावेदारी पेश करने के लिए तैयार हैं।

बीजेपी ने बड़े नेताओं और स्टारडम वाले उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। पूर्व सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, राजीव प्रताप रुडी, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, सतीश चंद्र दुबे, सुशील सिंह, आरके सिंह, अश्विनी चौबे, मिथिलेश तिवारी, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव और शाहनवाज हुसैन जैसे वरिष्ठ नेता चुनावी रणभूमि में उतर सकते हैं। इसके अलावा खिलाड़ी, नौकरशाह और फिल्म जगत से जुड़े सितारे भी पार्टी की तरफ से चुनावी रणनीति का हिस्सा बनेंगे। हाल ही में पवन सिंह और आईपीएस आनंद मिश्रा बीजेपी में शामिल हुए हैं और संभावित उम्मीदवारों में गिने जा रहे हैं।

बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक ने कहा कि बैठक में प्रत्याशियों के नामों के अलावा कई अहम मुद्दों और चुनावी रणनीतियों पर मंथन होगा। पार्टी की कोशिश है कि सीटों का संतुलन बनाए रखते हुए योग्य और लोकप्रिय उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए। इस बैठक के बाद पार्टी की अंतिम सूची और टिकट वितरण पर अंतिम मुहर लगेगी, जिससे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तस्वीर साफ़ होने लगेगी।

भ्रष्टाचार के आरोप में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो जजों को निलंबित किया

बिहार में मूसलाधार बारिश से तबाही, घर ढहे और सड़के जलमग्न

रोहतास, पटना और सारण। बिहार में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। कई जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करना पड़ा, किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और सड़कें पानी में डूब गईं। पटना के कई गली-मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

रोहतास जिले में हालात सबसे गंभीर हैं। पहाड़ी इलाकों से बहते बारिश के पानी ने आसपास के कई गांवों को जलमग्न कर दिया है। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। डेहरी के ASP अतुलेश झा भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं।

रेलवे ट्रैक पर भी पानी चढ़ गया है, जिससे ट्रेनों को धीमी गति से चलाया जा रहा है। ग्रैंड कार्ड रेल सेक्शन के सासाराम, करवंडिया और डेहरी आसपास ट्रैक पर बारिश का पानी जमा होने के कारण रेलवे को पानी हटाने के लिए विशेष कवायद करनी पड़ रही है।

वार्ड नंबर 28 के प्रतापगढ़ मोहल्ला में 20 कच्चे मकान गिर गए हैं। कई महिलाओं और बच्चों को चोटें आई हैं, और उनके परिवारों को भारी नुकसान हुआ है। डेहरी अनुमंडल प्रशासन ने सोन नदी के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया है।

जिले के अन्य हिस्सों में भी कई कच्चे मकान ढहने की खबरें सामने आई हैं। जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज का पूरा परिसर डूब गया है, वहीं 100 से अधिक कारें पानी में डूब गई हैं। सरकारी कार्यालय और विद्यालय भी जलमग्न हैं, और सड़कों पर लगातार पानी बह रहा है।

शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्होंने इतनी भारी बारिश पहले कभी नहीं देखी। जिला प्रशासन ने स्थिति को गंभीर मानते हुए अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।

बिहार में इस मौसमी आपदा से लोगों के घर, फसलें और सड़कें प्रभावित हुई हैं, और प्रशासन ने राहत कार्यों और बचाव प्रयासों को प्राथमिकता दी है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राहत शिविरों की स्थापना और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने का काम जारी है।

जुबीन गर्ग की मौत पर उठे नए सवाल: साथी ने लगाया मैनेजर और ऑर्गनाइज़र पर जहर देने का आरोप

असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में अब तक जो तस्वीर सामने आई थी, उसमें यह घटना एक हादसा मानी जा रही थी। लेकिन अब उनके बैंडमेट और साथी गायक शेखर ज्योति गोस्वामी के बयान ने इस पूरे केस को नया मोड़ दे दिया है। शेखर, जो इस समय पुलिस की गिरफ्त में है, ने कहा है कि जुबीन की मौत के पीछे उनके अपने मैनेजर और इवेंट ऑर्गनाइज़र की गहरी साजिश थी।

शेखर ने पुलिस को दिए बयान में दावा किया कि जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और इवेंट ऑर्गनाइज़र श्यामकनु महंत ने मिलकर उन्हें जहर दिया और फिर इस हत्या को हादसा बताने की योजना बनाई। शेखर ने कहा कि वह सिंगापुर में जुबीन के आखिरी सफर में उनके साथ था और उसने अपनी आंखों से कई अजीब घटनाएं देखीं। उसके अनुसार, पैन पैसिफिक होटल में रहने के दौरान ही उसने महसूस किया था कि मैनेजर शर्मा का व्यवहार असामान्य हो चुका था। वह लगातार जुबीन पर नजर रख रहा था और कई बार अलग-अलग लोगों से चुपचाप बातें करता देखा गया।

सबसे चौंकाने वाला वाकया समुद्र के बीच हुआ, जब जुबीन और उनका दल याट (नाव) से बाहर गया था। शेखर ने बताया कि उस समय नाव के असली चालक को हटाकर खुद मैनेजर शर्मा ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। यात्रा के दौरान अचानक जुबीन की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और वे हांफ रहे थे। शेखर ने कहा कि उस समय सभी लोग परेशान हो गए थे, लेकिन मैनेजर शर्मा बिल्कुल ठंडेपन से बोला— "जाबो दे, जाबो दे" यानी "उसे जाने दो, उसे जाने दो।" यह सुनकर शेखर को यकीन हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और जुबीन को बचाने के बजाय उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है।

जुबीन गर्ग, जिन्हें असम का "रॉकस्टार" कहा जाता था, सिर्फ गायक ही नहीं बल्कि संगीतकार और अभिनेता के रूप में भी बेहद लोकप्रिय थे। उनकी आवाज़ ने न सिर्फ उत्तर-पूर्व बल्कि पूरे भारत में उन्हें लाखों प्रशंसक दिए थे। उनकी अचानक मौत ने पूरे असम और संगीत जगत को हिला दिया था। लोग इस बात को एक हादसा मानकर ग़मगीन थे, लेकिन अब शेखर के खुलासे ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है।

पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। शेखर के बयान के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सचमुच जुबीन गर्ग की मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि योजनाबद्ध हत्या थी। अगर शेखर के आरोप सही साबित होते हैं, तो यह केस असम के संगीत इतिहास की सबसे बड़ी साजिश साबित हो सकता है। फिलहाल, जांच एजेंसियां जुबीन के मैनेजर और ऑर्गनाइज़र दोनों से पूछताछ की तैयारी में हैं और पुलिस सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।

रेनॉल्ट में बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी, 3,000 पदों पर मंडरा रहा खतरा

नई दिल्ली। फ्रांसीसी ऑटोमोबाइल कंपनी रेनॉल्ट ने लागत घटाने और संचालन को सरल बनाने के लिए कर्मचारियों की छंटनी की योजना पर विचार शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी वैश्विक स्तर पर करीब 3,000 पदों में कटौती कर सकती है। इस कदम का असर मुख्य रूप से सहायक सेवाओं पर पड़ेगा, जिनमें मानव संसाधन, वित्त और मार्केटिंग जैसे विभाग शामिल हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन विभागों में लगभग 15% पद समाप्त हो सकते हैं।

कंपनी ने हालांकि अभी अंतिम निर्णय की पुष्टि नहीं की है। रेनॉल्ट के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी फिलहाल विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है और इस चरण में किसी निश्चित संख्या का खुलासा करना जल्दबाजी होगी। लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया कि कंपनी कार्यान्वयन की गति बढ़ाने, संचालन को सरल बनाने और निश्चित लागतों को अनुकूलित करने की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहती है।

रेनॉल्ट के सामने मौजूदा चुनौती केवल आंतरिक लागत ही नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार माहौल भी है। अमेरिका के टैरिफ से कंपनी सीधा प्रभावित नहीं हुई है क्योंकि वह अमेरिकी बाजार में अपनी कारें नहीं बेचती, लेकिन यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों पर पड़े दबाव का असर अप्रत्यक्ष रूप से रेनॉल्ट पर भी पड़ा है। अमेरिकी व्यापार बाधाओं ने यूरोपीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को और कठिन बना दिया है, वहीं चीनी कंपनियों ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिससे रेनॉल्ट पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है।

कंपनी की 70% से अधिक बिक्री फिलहाल यूरोप में होती है, जहां बाजार में विकास की गति धीमी है। ऐसे में रेनॉल्ट के लिए अब उभरते बाजारों में प्रवेश और विस्तार करना अनिवार्य हो गया है। इसी रणनीति के तहत कंपनी ने घोषणा की है कि वह 2027 तक गैर-यूरोपीय बाजारों के लिए आठ नए मॉडल पेश करेगी और इस दिशा में 3 अरब यूरो (करीब 3.4 अरब डॉलर) का निवेश करेगी। रेनॉल्ट की यह संभावित छंटनी न केवल उसके कर्मचारियों के भविष्य पर असर डालेगी, बल्कि यह संकेत भी है कि वैश्विक ऑटो उद्योग किस तेजी से बदलते माहौल में काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की दौड़ में आगे बने रहने और लागत पर नियंत्रण रखने के लिए कंपनी को कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं।

पति को उतारा मौत के घाट: घरेलू प्रताड़ना से टूटी पत्नी ने की खौफनाक हत्या

वाराणसी। लल्लापुरा इलाके में शुक्रवार को मदरसा शिक्षक दानिश की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। शनिवार को पुलिस ने इस रहस्यमयी हत्या का खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि दानिश की हत्या उसकी पत्नी रुबीना ने ही की। पुलिस पूछताछ में रुबीना ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि पति की रोज़मर्रा की प्रताड़ना ने उसे इतना तोड़ दिया था कि उसने मौत का रास्ता चुन लिया।

40 वर्षीय दानिश एक मदरसे में सरकारी शिक्षक थे। पढ़ा-लिखा परिवार होने के बावजूद घर की आर्थिक हालत खराब थी। लेकिन असली समस्या दानिश की आदतें थीं। पत्नी रुबीना के अनुसार, दानिश रोज़ शराब पीकर घर लौटता और किसी न किसी बात पर उसे बेरहमी से पीटता था। घर के अन्य सदस्य भी उसके समर्थन में रहते, जिससे रुबीना को न्याय और सहारा कहीं से नहीं मिलता।

रुबीना ने पुलिस को बताया कि गुरुवार की रात भी दानिश ने उसे बुरी तरह मारा-पीटा। यहां तक कि बेटा भी मजाक उड़ाता था और धमकाता था कि अगर

कुछ कहोगी तो पापा से कह दूंगा और वह तुम्हें और मारेंगे। इस माहौल ने रुबीना का धैर्य पूरी तरह तोड़ दिया। उसी रात उसने अपने पति की हत्या का फैसला कर लिया।

पुलिस पूछताछ में रुबीना ने कबूल किया कि जब दानिश गहरी नींद में सो रहा था, तब उसने पहले सिल के बट्टे से उसके सिर पर लगातार कई वार किए। जब वह अधमरा हो गया, तो रुबीना ने घर में रखा चाकू उठाया और उसका गला रेत दिया। इसके बाद भी उसने चाकू से उसके सिर और चेहरे पर कई वार किए ताकि वह बिल्कुल भी जिंदा न बचे।

एसीपी चेतगंज डॉ. ईशान सोनी ने बताया कि देर रात तक चली पूछताछ में रुबीना ने हत्या की वारदात स्वीकार कर ली। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल सिल का बट्टा और चाकू बरामद कर लिया गया है।

इस सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है। लोग हैरान हैं कि घरेलू प्रताड़ना और रोज़ की मारपीट किस हद तक किसी महिला को अंदर से तोड़ सकती है कि वह खुद ही अपने जीवनसाथी की हत्यारिन बन जाए।

शीशमहल का नया रूप: दिल्ली का 'गेस्ट हाउस' बनेगा पूर्व मुख्यमंत्री आवास, आम जनता को भी मिलेगी एंट्री

दिल्ली का 6, फ्लैग रोड स्थित वही बंगला, जिसे कभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक निवास कहा जाता था और जिस पर 45 करोड़ रुपये की मरम्मत और साज-सज्जा को लेकर सियासत खूब गर्माई थी, अब एक बिल्कुल नए किरदार में सामने आने जा रहा है। सरकार ने इस आलीशान बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने की योजना बनाई है। अधिकारियों का कहना है कि इसके नवीनीकरण के बाद यह न सिर्फ सरकारी मेहमानों और अधिकारियों के ठहरने की जगह बनेगा, बल्कि आम जनता के लिए भी कुछ हिस्से खोले जाएंगे। योजना के मुताबिक इस गेस्ट हाउस में आधुनिक सुविधाएं होंगी—जैसे विशाल पार्किंग एरिया, कैफेटेरिया, वेटिंग हॉल और मीटिंग रूम। यहां आने वाले मेहमान पारंपरिक भारतीय भोजन का स्वाद ले सकेंगे। इसके रख-रखाव के लिए करीब 10 कर्मचारियों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। कहा जा रहा है कि इसे दिल्ली सरकार के गेस्ट हाउस नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाएगा, जहाँ मंत्री और अधिकारी तय किराये पर ठहर सकेंगे। यह वही बंगला है जिसे भाजपा ने व्यंग्य में "शीशमहल" नाम दिया था। दरअसल, साल 2022 में जब इस बंगले के नवीनीकरण पर लगभग 45 करोड़ खर्च किए गए थे, तब भाजपा ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया था। चुनावी मंचों से लेकर सदन तक इस पर तीखी बहस छिड़ी थी। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया था कि दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा फिजूलखर्ची में लगाया गया है। विवाद इतना गहरा हुआ कि उस समय दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विजिलेंस विभाग से जांच कराने के आदेश दिए। बाद में भाजपा विधायक और तत्कालीन विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच शुरू हुई, जो अभी भी जारी है। अब जबकि यह बंगला आम लोगों और सरकारी मेहमानों के लिए गेस्ट हाउस में तब्दील होने जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में फिर हलचल तेज हो गई है। समर्थकों का मानना है कि यह कदम दिल्ली की जनता को सीधे लाभ देगा और आलीशान संपत्ति का सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित करेगा, जबकि विरोधियों का कहना है कि यह केवल पुरानी गलतियों को ढकने की कोशिश है। बहरहाल, शीशमहल अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाज़ी का प्रतीक न रहकर, दिल्ली के गेस्ट हाउस नेटवर्क का हिस्सा बनने की ओर बढ़ रहा है। अगर यह योजना मंजूर हो गई, तो जल्द ही आम लोग भी उस बंगले में प्रवेश कर सकेंगे, जिसे कभी दिल्ली की सियासत का सबसे चर्चित पता कहा जाता था।

पाकिस्तान से लगातार विदा ले रहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, रोजगार और अर्थव्यवस्था पर गहराया संकट

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) पर गहरा असर डाल रहे हैं। अमेरिकी दिग्गज कंपनी प्रॉक्टर एंड गैंबल (पीएंडजी) ने हाल ही में पाकिस्तान में अपना उत्पादन रोकने का ऐलान किया, जबकि इसकी सहायक कंपनी जिलेट ने भी कारोबार समेट लिया है। कभी शेविंग से जुड़े उत्पादों के लिए मशहूर जिलेट का राजस्व दो साल में घटकर केवल तीन अरब पाकिस्तानी रुपये रह गया। इससे पहले उबर, एलि लिली, यामाहा मोटर्स जैसी 10 से अधिक कंपनियां भी पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं। पीएंडजी पाकिस्तान में बच्चों के डायपर और अन्य बुनियादी उपभोक्ता उत्पाद बनाती थी, जबकि जिलेट रेजर, क्रीम, फोम और ब्लेड तैयार करती थी। इनके बंद होने से अब आम लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की आपूर्ति पर संकट मंडरा रहा है।

पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल (पीबीसी) के पूर्व सीईओ एहसान मलिक का कहना है कि कंपनियों को कीमतों में बढ़ोतरी की मंजूरी नहीं मिली और बौद्धिक संपदा अधिकारों का पालन भी सही तरीके से नहीं हो रहा था। यही कारण है कि कई कंपनियों ने पाकिस्तान छोड़ने का निर्णय लिया। हालांकि, विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि कुछ कंपनियां अपनी वैश्विक रणनीतियों के चलते भी जा रही हैं।

दूसरी तरफ, पाकिस्तान में पहले से ही ब्रेन ड्रेन की समस्या गहराती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले तीन साल में 10 लाख से ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर और अकाउंटेंट विदेश पलायन कर चुके हैं। हाल ही के एक सर्वे में 40% युवाओं ने माना कि वे पाकिस्तान छोड़कर बाहर काम करना चाहते हैं। पीएंडजी के उत्पादन बंद करने से भी हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। युवा वर्ग खासतौर पर महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा है। औसतन 50 हजार से दो लाख रुपये कमाने वाले युवाओं के लिए जीवन-यापन मुश्किल हो गया है। भारत और बांग्लादेश की तुलना में पिछले पांच वर्षों में पाकिस्तान में जरूरी वस्तुओं की कीमतें तीन से चार गुना बढ़ चुकी हैं। सरकार भी अब विदेशी रेमिटेंस पर निर्भर होती जा रही है। विदेशों में काम कर रहे पाकिस्तानी हर साल लगभग 30 अरब डॉलर भेजते हैं, जिससे कई परिवारों का जीवन चलता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, एमएनसी देश के राजस्व में लगभग 20% और रोजगार में 5% से अधिक का योगदान देती थीं।

पिछले दो वर्षों में कई दिग्गज कंपनियां पाकिस्तान को अलविदा कह चुकी हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद जुलाई 2024 में काम बंद किया। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर ने मई 2024 में कराची स्थित अपना प्लांट बेच दिया। शेल ग्लोबल ने नवंबर 2023 में शेल पाकिस्तान लिमिटेड से पूरी हिस्सेदारी बेची। फ्रांस की टोटल एनर्जी और नॉर्वे की टेलीनॉर भी क्रमशः 2024 और 2022 में पाकिस्तान से बाहर निकल चुकी हैं।

लगातार कंपनियों का पाकिस्तान से जाना न केवल रोजगार पर संकट पैदा कर रहा है, बल्कि यह देश की आर्थिक स्थिति और वैश्विक छवि के लिए भी गंभीर चुनौती बन गया है।

गुजरात भाजपा को मिला नया ओबीसी अध्यक्ष: जगदीश विश्वकर्मा पर शाह-मोदी का भरोसा

गुजरात की राजनीति में शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नया चेहरा सामने लाकर सियासी समीकरण बदल दिए। पार्टी ने सी.आर. पाटिल की जगह भूपेंद्र पटेल सरकार में राज्य मंत्री और अमित शाह के बेहद करीबी माने जाने वाले 52 वर्षीय जगदीश विश्वकर्मा को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। अहमदाबाद शहर से यह जिम्मेदारी संभालने वाले वे पहले नेता हैं और साथ ही ओबीसी वर्ग से आने वाले दूसरे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं।

सुबह जगदीश विश्वकर्मा ने अहमदाबाद के कैंप हनुमान मंदिर में दर्शन-पूजन किया और उसके बाद गांधीनगर स्थित भाजपा मुख्यालय 'कमलम' पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक गाजे-बाजे के साथ उनका स्वागत किया। माहौल किसी उत्सव से कम नहीं था। मुख्यालय में आधिकारिक घोषणा के बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया।

गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने इस मौके पर कहा कि जगदीश विश्वकर्मा हमेशा से जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी वे कार्यकर्ताओं के बीच उसी आत्मीयता से काम करेंगे। उनका मानना है कि विश्वकर्मा राज्य के हर वर्ग, समाज और क्षेत्र के विकास के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेंगे।

इस नियुक्ति के पीछे भाजपा की गहरी रणनीति झलकती है। पाटीदार और अन्य ओबीसी समुदायों के दबाव के बीच पार्टी को ऐसा चेहरा चाहिए था, जो न केवल संगठनात्मक रूप से मजबूत हो, बल्कि सभी समुदायों में स्वीकार्यता भी रखता हो। पिछले कई हफ्तों से इस पद को लेकर अंदरूनी खींचतान चल रही थी। पाटीदार, क्षत्रिय, ब्राह्मण, अहीर, ठाकोर और कोली जैसे प्रभावशाली समूहों के नेताओं ने अपनी-अपनी दावेदारी पेश की थी। कांग्रेस से आए दलबदलुओं ने भी पैरवी की थी। लेकिन आखिरकार दिल्ली हाईकमान ने ऐसा चेहरा चुना, जिस पर शाह और मोदी दोनों को भरोसा है और जिसे संगठन में एक तटस्थ, सर्वमान्य नेता माना जाता है।

जगदीश विश्वकर्मा की नियुक्ति को भाजपा के 2027 विधानसभा चुनाव और उससे पहले 2026 के निकाय चुनावों की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। पार्टी का मानना है कि ओबीसी समुदायों के साथ-साथ शहरी मतदाताओं में भी विश्वकर्मा की पकड़ मजबूत है, जो भाजपा की चुनावी रणनीति को संतुलन देने में सहायक होगी।

इस कदम से साफ संदेश गया है कि भाजपा गुजरात में संतुलित जातीय समीकरण साधते हुए अपने संगठन को और अधिक मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। शाह-मोदी का यह दांव कितना सफल होता है, यह तो आने वाले चुनाव बताएंगे, लेकिन अभी के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह और विपक्ष में चिंता का माहौल जरूर बना दिया है।